वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 2020–मार्च 2021
अप्रैल 2021–मार्च 2022

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

तकनीकी शिक्षा सदन,
बेज संख्या- 7-12, सेक्टर-04, पंचकुला
दूरभाष- 0172- 2580435, इमेल-hshecouncil@gmail.com

अनुक्रमणिका

	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन एवं कार्य	4-5
2.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का उद्देश्य	5-6
3.	परिषद् के लोगो का निर्माण	06
4.	उच्च शिक्षा में भविष्य के परिदृश्य - विजन दस्तावेज़	07-09
5.	हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन	09-10
6.	Youth4 Nation और परिषद् के संयुक्त तत्वधान में दिल्ली में बैठक आयोजित	10
7.	अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन	10-11
8.	परिवार पहचान पत्र योजना में परिषद् का योगदान	12
9.	हरियाणा में विश्वविद्यालय विषय पर कार्याशाला	12-13
10.	दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन	13-14
11.	कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन	14
12.	परिषद् की वेबसाइट का निर्माण	14
13.	प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लोकार्पण	15
14.	एनईपी रेडी रेकनर	15-16
15.	पीठों की प्रबंधन के लिए नीति-निर्धारण एवं मार्गदर्शिका	16
16.	प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोतर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों की समीक्षा	16
17.	अकादमिक लीडरशिप' कार्यशाला-1 का आयोजन	17
18.	लघु समायावधि के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्सवेयर	17
19.	प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के वेबसाइट में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने हेतु समिति का गठन	17
20.	दूरस्थ पाठ्यक्रम के लिए लिए क्षेत्राधिकार का निर्धारण	17-18
21.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित चेकलिस्ट	18
22.	4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या की रुपरेखा	18
23.	हरियाणा में उच्च शिक्षा परिदृष्य: स्थिति रपट	18
24.	राज्य के मेधावी प्राध्यापकों को सम्मान देने के लिए समिति का गठन	18-19
25.	ई-अध्ययन (डिजिटल शिक्षण के लिए स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम)	19
26.	विक्रमी संवत कैलेडर	19
27.	जीविकोपार्जन के उपायों का समावेश	20-22
28.	परिषद् कार्यालय में पुस्तक, पत्रिका एवं समाचार-पत्र का प्रबंधन हेतु पुस्तकालय की स्थापना	22
29.	सामान्य अधिनियम के मसौदे की समीक्षा के लिए अधिवक्ताओं की समिति का गठन	22

30.	अकादमिक परिषद में पूर्व विद्यार्थियों, पेशेवरों और अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करना	22
31.	नये महाविद्यालय स्थापित करने के लिए मानदंड सुझाने के लिए समिति का गठन	23
32.	उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना की समीक्षा	23
33.	शोध के आधुनिक क्षेत्रों का चयन	23
34.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन	23-24
35.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में नियुक्ति	24
36.	बजट का आवंटन	24
37.	परिषद् कार्यालय के लिए स्थान आवंटित	25
38.	परिषद् में वाहन की खरीद	25
39.	स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास	25
40.	स्नातक स्तर पर महाविद्यालयों में जीविकोपार्जन एवं जीवन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने बारे	25
41.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के पास प्रक्रियाधीन विषय	25-26
42.	शोध में नवाचार के उपाय	26
43.	विभागों का एकीकरण	26
44.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के लिए नियम और विनियम	26-27
45.	शिक्षा नीति के माध्यम से स्वच्छ और हरित हरियाणा को बढ़ावा देना	27-28
46.	बाहरी विशेषज्ञों के लिए टीए/डीए/सहभागिता शुल्क आदि	28
47.	हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना	29
48.	लघु समयावधि सर्टिफिकेट/डिप्लोम	29
49.	वर्टिकल कोर्स में प्रवेश के लिए बी. वोक डिग्री की पात्रता	29-30
50.	सुरक्षित परिसर चेकलिस्ट	30
51.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण	30-31
52.	राज्य के विश्वविद्यालयों में फ्लेक्सी परीक्षा प्रणाली/मांग पर परीक्षा का प्रयोग	31
53.	मीडिया में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की गतिविधियों की कवरेज	32-57
54.	अनुलग्नक - अनुलग्नक – 1 अनुलग्नक – 2 अनुलग्नक – 3 अनुलग्नक – 4 अनुलग्नक – 5	58-94

1. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन एवं कार्य

हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा 28 फरवरी, 2018 को पारित 'हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम संख्या 4/2018 जोकि हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2018 को अधिसूचित किया गया के अंतर्गत हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। यह परिषद राज्य में उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं की स्वायत्तता और वृहत् उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए नीति सूत्रीकरण, भावी योजना और सामाजिक न्याय प्रोन्नत करने के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की आवश्यकता के अनुसार राज्य की सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं के अनुसार उच्च शिक्षा के विकास के मार्गदर्शन और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक मामलों के लिए समर्पित है।

उपरोक्त अधिनियम में परिषद के 20 कर्त्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

(1) शिक्षा आयोग के निर्णयों को लागू करना।

(2) राज्य (भावी योजना, वार्षिक योजना तथा बजट) के लिए उच्च शिक्षा की नीतियां बनाना।

(3) योजना तथा कार्यान्यवन में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता करना।

(4) शीर्ष शिक्षा संस्थानों, नियामक निकायों और राज्य सरकार के बीच समन्वय करना।

(5) उच्च शिक्षा की योजनाओं का अधीक्षण तथा कार्यान्यवन करना।

(6) उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रबंध करना, सूचना प्रणाली बनाना तथा इसका रख-रखाव करना।

(7) सरकार के स्तर तथा संस्था के स्तर पर उच्चतर शिक्षा से संबंधित विषयों का डाटा समय-समय पर संग्रहण करना।

(8) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन द्वारा बनाई गई मूल अनुपालन सूचना के अनुसार राज्य में उच्च शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो मानदण्ड बनाना।

(9) राज्य में अध्यापन गुणवत्ता तथा अनुसंधान में निरंतर वृद्धि के लिए योजना बनाना तथा उपाय सुझाना।

(10) परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव देना।

(11) समसामयिक तथा सुसंगत पाठ्यक्रम बनाना।

(12) अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देना।

(13) राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्ता का संरक्षण,संवर्धन सुनिश्चित करना।

(14) नई संस्थाओं, महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना।

(15) मान्यता की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना।

(16) उच्च शिक्षा में निवेशों के लिए राज्य सरकार को मन्त्रणा देना।

(17) विनियमों तथा अध्यादेशों को बनाने में विश्वविद्यालयों को मन्त्रणा देना।

(18) राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के अंशदान के रूप में प्राप्त राशि का प्रबंध करना।

(19) ऐसी प्रक्रियाएं बनाना जिनके माध्यम से राज्य सरकार की सहायता-अनुदान उच्च शिक्षा संस्था को अंतरित की जा सकती है।

(20) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अधीन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों हेतु वित्तीय सहायता के अंतरण की पारदर्शी प्रक्रिया बनाना तथा अनुसरण करना।

इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 मार्च 2018 को जारी किये गये प्रशासकीय आदेशों की प्रति अनुलग्न अनुलग्नक 01 (पृष्ठ 07) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2020 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन अधिनियिम संख्या 12/2020 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जिसके अनुसार परिषद् के पुर्नगठन की अधिसूचना का प्रारूप सरकार के पास विचाराधीन है।

2. हरियाणा राज्य उच्च परिषद स्थापना का उद्देश्य

'हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018' का मसौदा पेश करते वक्त तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इस परिषद गठन के कारण और उद्देश्यों का रेखांकित किया। उनके द्धारा जो कहा गया, वह इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की योजना एवं समन्वय, स्वायत्त, निष्पक्ष राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के माध्यम से हो। राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हो जिसमें राज्य सरकार विश्वविद्यालय, शैक्षिक जगत एवं विशेषक्षों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसके द्धारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से उच्च शिक्षा के संबंध में समन्वय बन सके, जिसके द्धारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की उच्च स्तर की नियामक संस्थाओं के साथ सकारात्मक संबंधों का निर्माण हो सके।

परिषद की स्थापना से निम्न उद्देश्य पूर्ण होंगे:-

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण एवं भविष्य की योजनाएं बनाकर उच्च शिक्षा जगत में सामाजिक न्याय एवं उत्कृष्टता स्थापित हो सके।

(ख) राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता एवं दायित्वबोध की व्यवस्था बने।

(ग) राज्य एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा की दिशा एवं विकास की योजना निर्धारित हो सके।

3. परिषद् के लोगो का निर्माण

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद्
HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL
ज्योतिर्वृणीत तमसो विजानन्

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के फलस्वरूप लोगो बनवाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तदानुसार कार्यवाही करके परिषद् का लोगो तैयार करने तथा अपनाने बारे कार्यवाही संपन्न की गई।

4. उच्च शिक्षा में भविष्य के परिदृश्य – विजन दस्तावेज़

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा चयनित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सरकारी और सरकार की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक दिवसीय बैठक सह कार्यशाला का आयोजन 15.01.2020 को एक विजन पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया। इस कार्यशाला में अगले डेढ़ साल में अकादमिक क्षेत्र की कार्य योजना को केन्द्रीय विषय बनाया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक योजना का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सरकार को इनपुट प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग किया गया था।

बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल थे:-

(1) हमारी अकादमिक योजना हर साल जुलाई से जून के आधार पर होनी चाहिए न कि कैलेंडर वर्ष/वित्तीय वर्ष के आधार पर।

(2) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए सप्ताह में छह दिन के बजाय पांच दिन कार्य दिवस रख सकते हैं।

(3) समीक्षा समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रपट को परिषद की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

(4) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि स्नातक के बाद प्रत्येक छात्र आजीविका सीखने में सक्षम है।

(i) IT,

(ii) संचार,

(iii) व्यक्तित्व विकास,

(iv) छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के साथ परियोजना आधारित शिक्षा का एकीकरण आवश्यक है।

(5) केन्द्रीय सहायता से डीसीआरयूएसटी, मुरथल में प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्रों में अटल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। छात्रों को प्राप्त होने वाले महत्व और लाभों को देखते हुए, सभी छात्रों की सुविधा और कवरेज के लिए राज्य के वित्त पोषण के साथ इसी तरह के केंद्र को राज्य में किसी अन्य चिन्हित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए।

(6) स्थानीय जरूरतों के लिए अनुसंधान के लिए स्टेट रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाए।

(7) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष रूप से पीपीपी के माध्यम से संसाधन सृजन के लिए कार्य करना चाहिए ।

(8) छात्रों के लिए लागू एक आवेदक- एक स्टार्ट-अप योजना को प्राध्यापकों के लिए भी लागु किया जाए।

(9) उचित समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पीजी स्तर पर शुरू किए नए पाठ्यक्रम के कोर्स यूजी स्तर भी शुरू किए जाएं।

(10) दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान की जाए ताकि इसे अधिकतम छात्रों को उपलब्ध कराया जा सके।

(11) 2021 तक दस से बीस प्रतिशत अध्यापन नियमित शिक्षकों के अलावा बाहरी शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध शिक्षण के लिए स्वीकृत संख्या वास्तविक मानदण्ड से दस प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। 2021 तक ज्यादातर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स बजट के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे।

(12) उच्च शिक्षा के लिए समान वितरण और पहुंच की आवश्यकता है। इस संबंध में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों को भी कवर किया जाना चाहिए है।

(13) सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों में उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विकलांग बच्चों की भागीदारी के लिए अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

(14) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय प्रति छात्र प्रति सप्ताह न्यूनतम 20-25 घंटे सीखने को सुनिश्चित करेंगे। शिक्षण प्रक्रियाओं को अधिकतम सीमा तक डिजिटल किया जा सकता है।

(15) विश्वविद्यालय 2021 तक डिग्री के संग्रह प्रणाली को सुनिश्चित और लागू कर सकते हैं।

(16) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रति सेमेस्टर 50 घंटे खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस अवधि को परिसर में बिताने के कारण छात्रों को क्रेडिट दिया जा सकता है।

विजन का सार है:-

क. हमारे स्नातकों को आजीविका सीखने में सक्षम बनाएं।

ख. शासन को पारदर्शी बनाया जाये।

ग. राज्य अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाये।

घ. अटल केंद्र की तर्ज पर राज्य केंद्र की स्थापना ।

ड़. उद्योग के साथ अधिक संपर्क बने।

च. शिक्षकों के लिए स्टार्ट अप कार्यक्रम भी शुरू किये जाये।

छ. संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को एकीकृत किया जाये।

ज. यूजी स्तर पर नए पीजी पाठ्यक्रमों की शुरुआत हो।

झ. शिक्षकों के लिए अधिक व्यावहारिक ज्ञान आधारित प्रशिक्षण हो।

ट. स्वीकृत पद के अतिरिक्त दस प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित हो।

ठ. ड्रग फ्री कैंपस बने।

ढ. सप्ताह में शिक्षण के लिए 5 दिन का पालन किया जाये।

ड. छात्रों के बीच सॉफ्ट स्किल प्रदान करने के लिए विशेष भर्ती की जाये।

ण. सीएम 20 पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप सृजित हो।

त. सीएम 20 डॉक्टरेट फेलोशिप सृजित हो।

थ. स्वायत्त कॉलेजों के रुप में विकसित किए जाने वाले चयनित कॉलेजों की क्षमता की पहचान की जाये।

द. क्लस्टर विश्वविद्यालयों की संभावनाओं को तलाशा जाये।

वित्तीय निहितार्थ वाली अधिकांश सिफारिशों को 2020-2021 के वार्षिक बजट के मसौदे में शामिल किया गया और राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। हालांकि, कोविड-19 के वातावरण के कारण इसे अपडेट करना अपेक्षित है। परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के साथ नियमित अनुवर्तन किया जा रहा है कि योजनाओं को क्यों और किस कारणों से वार्षिक बजट में शामिल करना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021- 22 के दौरान विशेष प्रावधान करने का प्रयास किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग से भी वार्षिक योजनाओं का मसौदा तैयार करते समय परिषद के साथ परामर्शी प्रक्रिया करने का अनुरोध किया गया है।

5. हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने 18.08.2020 से 21.08.2020 तक चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन और समापन समारोह की अध्यक्षता हरियाणा के माननीय राज्यपाल कुलाधिपति ने की। इसमें 250 से अधिक शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और कुलपति, सहायता प्राप्त और निजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, कुलपति और अन्य अधिकारी और अन्य शिक्षाविदों ने ऑनलाइन भाग लिया। विचार-विमर्श में सत्तर शिक्षाविदों/विशेषज्ञों ने सक्रिय रुप से भाग लिया। उन्नीस प्रस्तुतियाँ दी गईं। हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिशों के साथ-साथ

कार्यशालाओं की विस्तृत रपट 21.08.2020 को माननीय राज्यपाल कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई थी। संबंधित अधिकारियों को उनके अवलोकन और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशों को राज्य सरकार के साथ भी साझा किया गया है। सिफारिशों के साथ रपट की एक प्रति परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकन के लिए अनुलग्नक 02 (पृष्ठ 09) पर दी गई है।

6. Youth4 Nation और परिषद् के संयुक्त तत्वधान में दिल्ली में बैठक आयोजित

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् और Mission Reach the Youth Group के संयुक्त तत्वाधान में 'Strategic Plan to Motivate Students for Rastra Bhakti and Aatmnirbharta' विषय पर हरियाणा भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 10.10.2021 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02.30 तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना जागृत करने हेतु इस संस्था जिसमें Defense veterans, Scientists, Academia, Bureaucrats आदि शामिल है के Motivational Experiences Show करने का निर्णय लिया गया।

7. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन

भारतीय मातृभाषाओं का साहित्य सृजनात्मकता व राष्ट्रीयता के भावों से ओतप्रोत है। ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन भारतीय मातृभाषाओं के प्रचार-प्रसार से ही संभव है। मातृभाषा मनुष्य के लिए गर्व का विषय है। मातृभाषा अपने हाव, भाव और अपने आप को दूसरों के सामने रखने का साधन प्रदान करती है। मातृभाषा को सीखने के लिए किसी कक्षा की जरुरत नहीं पड़ती। मातृभाषा स्वत: ही अपने परिजनों द्वारा उपहार स्वरुप मिलती है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है।

किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए अपनी मातृभाषा अपनी पहचान की तरह होती है। इसको बचाकर रखना बेहद आवश्यक होता है। आज विश्व में ऐसी कई भाषाएं और बोलियां है जिनका संरक्षण आवश्यक है। लोकभाषाओं की चिंता इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी विरासत का एक भाग हैं और हमारी थाती हैं और इनमें जो भी कुछ सुंदर और श्रेष्ठ रचा जा रहा है, उसे सहेजकर

रखा जाना चाहिए। इसीलिए यूनेस्को महासभा ने नवंबर 1999 में दुनिया की मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए साल 2000 से प्रति वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया हैं।

भारतवर्ष में भाषाओं की विविधता का पुष्पगुच्छ अपनी सुगंध बिखेर रहा है। शिक्षा जगत में भाषा-शिक्षण पर प्रारंभ से ही विशेष बल दिया जाता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। असमिया, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि अपनी सभी राष्ट्रीय भाषाएं भारतीय संस्कृति की संवाहिका व पोषिका रही हैं। ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन भारतीय मातृभाषाओं के प्रचार-प्रसार से ही संभव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए मातृभाषाओं में पढ़ने-पढ़ाने एवं सीखने-सिखाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा को सर्वग्राहय एवं सहजता से अनुकरणीय बनाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण में मातृभाषाओं का समावेश नितान्त अपेक्षित है। एतदर्थ, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए अनुसंधान एवं विमर्श किये जा रहे है। इस तारतम्यता में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा सोमवार, 21 फरवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक दिवसीय प्रत्यक्ष और आभासी रूप दोनों रूप (Blended Mode) में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में पंजाबी और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान एवं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉ. हरमोहिंदर सिंह बेदी को प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉ. बेदी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के माननीय कुलाधिपति एवं हिंदी एवं पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान है। इस संगोष्ठी में प्रदेश के सभी शासकीय एवं नीजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शामिल हुए।

8. परिवार पहचान पत्र योजना में परिषद् का योगदान

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा CRID की आपसी सहभागिता में 4 जून, 2021 को परिवार पहचान पत्र के लाभ एवं कार्यान्वयन बारे एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 'परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)' और 'संपूर्ण पीपीपी अभ्यास के हिस्से के रूप में आय सत्यापन' विषयों पर संबोधित किया। बैठक में श्री वी. उमाशंकर, आईएएस, पीएससीएम ने हरियाणा के सरकारी तथा सहायता प्राप्त कॉलेज के उन छात्र स्वयंसेवकों का विवरण भेजने के लिए सरकार के सभी प्राचार्यों से अनुरोध किया। परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने बैठक में कहा कि आय सत्यापन कार्य का हिस्सा बनने के इच्छुक इस छात्र को इस अभियान में शामिल किया जाएगा जो उसी गांव या शहर में रहता है जिसमें आय सत्यापन किया जाना है। विवरण में छात्र स्वयंसेवक का नाम, आधार संख्या, उचित आवासीय पता और मोबाइल नंबर शामिल होना चाहिए। परिषद को 125 कॉलेजों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त) से 12,874 छात्र स्वयंसेवकों का डेटा प्राप्त हुआ और इसे नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) को भेज दिया गया।

9. हरियाणा में विश्वविद्यालय विषय पर कार्यशाला



हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से दिनांक 23 सितंबर



2021 को गुरुग्राम के नार्थकैप विश्वविद्यालय में एक दिन की कार्यशाला गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप परियोजना के तहत हरियाणा में विश्वविद्यालय विषय पर आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव ने सहभागिता की। कार्यशाला में हरियाणा के विश्वविद्यालयों एवं ब्रिटिश गणराज्य के विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू कर शैक्षणिक वातावरण को स्पर्धात्मक बनाने पर जोर दिया गया।

10. दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन

परिषद द्वारा 14 और 15 मई, 2022 को हरियाणा निवास, सेक्टर-3, चंडीगढ़ में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा 14.05.2022 को उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे और माननीय राज्यपाल, कुलाधिपति, हरियाणा 15.05.2022 को समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन में राज्य के पदाधिकारियों और 15 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया।

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन पर व्यापक चर्चा हुई, इनमें प्रमुख थे:- एनईपी-2020: स्थिति और योजना; समग्र और मूल्य आधारित शिक्षा; विश्वविद्यालयों द्वारा प्लेसमेंट, स्व-रोजगार, उद्यमिता और ऊष्मायन पहल; पोस्ट कोविड और एनईपी इको सिस्टम और विश्वविद्यालय के प्रबंधन से संबंधित मामले जैसे प्रशासन, परीक्षा, शिक्षण, वित्त आदि।

सम्मेलन के दौरान लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:

• उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभागों का विलय होना चाहिए।

• हरियाणा सरकार के विभाग अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइनिंग, परामर्श कार्य आदि जैसे कार्यों को विश्वविद्यालयों को आउटसोर्स करेंगे।

• प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षणिक कलैण्डर में पूर्व छात्र दिवस के रूप में एक दिन निर्धारित करेगा, पूर्व छात्र संघ के लिए एक समारोह (मेला) आयोजित करेगा।

• एनईपी के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की नियमित निगरानी करना।

• विश्वविद्यालयों में 03 महीने से अधिक समय से लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों को एक केंद्रीय समिति द्वारा संबोधित किया जाएगा जिसमें वित्त विभाग, संबंधित विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के प्रत्येक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रशासनिक और वित्तीय मामले उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा शैक्षणिक मामले हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के परामर्श से निपटाये जाये।

11. कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था पर आधारित दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक अंग्रेजी में "Managing Education Post Covid: Challenges & Opportunities" और हिंदी में "कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था चुनौतियां एवं संभावनाएं" है।

12. परिषद् के वेबसाइट का निर्माण

हरियाणा के विश्वविद्यालयों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों, पात्रता शर्तों, अवधि, करियर विकल्पों आदि के बारे में जानकारी को एक ही वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा www.hshec.org नया वेबसाइट बनाया गया है। इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 16 जून, 2021 को लांच किया गया।

13. प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लोकार्पण

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लोकार्पण समारोह दिनांक 30 जुलाई 2021 को लोकनिर्माण विभाग विश्राम गृह पंचकुला में किया गया। इस



लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे। समारोह में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा सरकार के शिक्षामंत्री श्री कंवर पाल , महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के विभागाध्यक्षों एवं प्रशासनिक सचिवों की गरिमामयी उपस्थिति थी। इस अवसर पर समारोह के विशिष्ठ अतिथि भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री एवं प्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री मुकुल कानिटकर ने प्रदेश के सभी उपस्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, विद्यालयीन शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को संबोधित किया। इसमें लगभग सात हजार शिक्षक एवं अन्य विद्वतजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मोड में उपस्थित रहें।

14. एनईपी रेडी रेकनर

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, संकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों आदि जैसे हितधारकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 के प्रत्येक अनुशंसा की त्वरित और आसान समझ के लिए सारणीबद्ध रूप में एक एनईपी रेडी रेकनर तैयार किया है।

15. पीठों की प्रबंधन के लिए नीति-निर्धारण एवं मार्गदर्शिका

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों की संरचना एवं शैक्षिक कार्यों की समीक्षा हेतु विश्वविद्यालय समीक्षा समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी। समिति द्वारा फरवरी, 2017 में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर दी थी। इसमें एक अनुशंसा विश्वविद्यालयों में पीठ प्रबंध के बारे में थी। इसके अतिरिक्त स्थापित पीठों के द्वारा संचालित शोध कार्यों, उनकी अवधि, प्रबंधन और संरचना पर समय-समय पर चर्चा होती रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह थी। इस विषय पर एक गहन विचार-विमर्श उपरांत इनकी स्थापना, संसाधन जुटाने, अवधि निश्चित करने इत्यादि बारे मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जाएं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने इस पर विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के उपरांत और विश्वविद्यालय समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रपट को भी ध्यान में रखते हुए इनकी स्थापना, अवधि, नीति-निर्धारण की प्रक्रिया, प्रबंधन एवं संसाधन जुटाने इत्यादि बारे एक मार्गदर्शिका तैयार की है।

16. प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोतर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों की समीक्षा

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा तीन सदस्यों की एक समिति का का गठन किया था। सदस्यों द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं इस संबंध में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णयों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन के पश्चात समिति ने अपनी रपट प्रस्तुत की है। इस रपट में माननीय न्यायालय में हुए फैसलों को भी संदर्भित किया गया है।

समिति द्वारा प्रस्तुत रपट में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। यह रपट मुख्यत: स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समस्याओं की पहचान एवं समस्याओं के समाधान के लिए सुझावों पर आधारित है।

17. अकादमिक लीडरशिप' कार्यशाला-1 का आयोजन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में दिनांक 08/10/2021 को प्रदेश के शासकीय पोषित विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के दायित्व बोध पर आधारित 'अकादमिक लीडरशिप' एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दस विश्वविद्यालयों के कुलसचिव उपस्थित थे। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजवीर सिंह उपस्थित थे।

18. लघु समायावधि के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्सवेयर का निर्माण

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा इस विषय पर सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों ने उद्देश्यपूर्ति के लिए पांच बैठके आयोजित की। समिति द्वारा प्रस्तुत रपट परिषद् की अनुशंसायें सरकार के अवलोकन के उपरांत उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई । अनुशंसाओं में महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि वर्तमान अपेक्षाओं एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के लिए उनके द्वारा पढ़े जाने वालों विषयों की applied Learning के तौर पर लघु अवधि के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा भी प्रदान की जायें।

19. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के वेबसाइट में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने हेतु समिति का गठन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा हरियाणा के निजी विश्वविद्यालयों के बीच छात्रों, संकायों और अन्यों के लिए प्रासंगिकता के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट का चयन करने के लिए समिति का गठन किया गया था। बैठक के बाद समिति द्वारा परिषद् को अपनी रपट प्रस्तुत कर दी गई तथा इस बारे में विश्वविद्यालयों के लिए अपने-अपने वेबसाईट को अधिक से अधिक विद्यार्थी उपयोगी बनाने हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई।

20. दूरस्थ पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्राधिकार का निर्धारण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ऐसे विद्यार्थियों के लिए जोकि किन्ही कारणों से उच्च शिक्षा नियमित रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हो तथा GER बढ़ाने के उद्देश्यों से

विश्वविद्यालयों के द्वारा दूरस्थ अध्ययन के लिए क्षेत्राधिकार बढ़ाने बारे संबंधित विश्वविद्यालयों की सहभागिता से विचार-विमर्श चल रहा है।

21. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित चेकलिस्ट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करन के लिए योग्य बिंदुओं के बारे में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयोंऔर राज्य के विभागों को मार्गदर्शन करने के लिए और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसे 03 भागों में विभाजित किया गया है।

1. विश्वविद्यालयों के लिए चेकलिस्ट
2. महाविद्यालयों के लिए चेकलिस्ट
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की चेकलिस्ट

22. 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या की रुपरेखा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2022 में दिए गए 4-वर्षीय डिग्री प्रोग्राम और मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सिस्टम जैसे निर्णयों को लागू करने के लिए, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम करिकुलम फ्रेमवर्क (UGPCF) तैयार किया है।

23. हरियाणा में उच्च शिक्षा परिदृश्य- स्थिति रपट

हरियाणा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए स्थिति रपट तैयार की गई है और इसे माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है।

24. राज्य के मेधावी प्राध्यापकों को सम्मान देने के लिए समिति का गठन

हरियाणा प्रदेश के सभी राज्य पोषित विश्वविद्यालय, राजकीय एवं राज्य सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों की सेवाओं को सम्मान देने के लिए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने राज्य पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करने और पुरस्कार विजेताओं द्वारा निर्धारित प्रदर्शन और गुणवत्ता आयामों को आत्मसात करने

में मदद करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के 05 वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक समिति का गठन किया है समिति ने प्रारूप तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

25. ई-अध्ययन (डिजिटल शिक्षण के लिए स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम)

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र में ज्ञान के लिए अंत:विषय और व्यावहारिक दृष्टिकोण परियोजना की परिकल्पना की है और हमारे शिक्षकों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शिक्षण के लिए एक स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर शिक्षकों और संकाय सदस्यों को आईसीटी एकीकृत ऑनलाइन शिक्षण और नए ऑनलाइन शैक्षणिक उपकरण अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा। मॉड्यूल का पायलट आधार पर परीक्षण और उसमें सुधारात्मक उपाय करने के बाद राज्य के सभी शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की सलाह दी है। इस प्रयोजन हेतु परिषद् ने एसवीएसयू, पलवल के परामर्श से सेल्फ-लर्निंग कोर्सवेयर तैयार किया है ताकि शिक्षकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और शिक्षक-शिक्षण के लिए उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। राज्य के सभी प्राध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है।

26. विक्रमी सम्वंत कैलेंडर

परिषद् द्वारा विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुरूप कैलेंडर डिजाइन करना एवं इसे मुद्रित करवाना तय है।

हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है। भारत सरकार ने भी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र स्तर पर भाषा निदेशालय स्थापित कर कार्य कर रहा है। अत: नवाचारों के रूप में और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को पुर्नजीवित एवं पुर्नस्थापित करने हेतु यह यथोचित होगा कि परिषद् इस बारे में आवश्यक पहल करें।

इसमें हरियाणा सरकार द्वारा घोषित और संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देना प्रस्तावित है। इसमें प्रति पृष्ठ पर तस्वीरों का कोलाज और टेक्सट शामिल करने की प्रस्तावना भी है। कैलेंडर भारतीय माह के अनुसार बनाया गया है तथा मुद्रित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

27. जीविकोपार्जन के उपायों का समावेश

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विगत कुछ वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के सुझाव दे रहे है। इन सुझावों में दो मुख्य व्यावहारिक सुझाव जीविका-उपार्जन एवं जीवन मूल्यों से संबंधित है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा स्नातक स्तर की शिक्षा में जीविका-उपार्जन के व्यावहारिक पक्ष एवं मानवीय मूल्यों के समावेश के प्रयास किए गए हैं। परिषद् का मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता एवं योग्यता होनी चाहिए, जिससे वे स्वयं जीवन चलाने के लिए सक्षम हो। नौकरी व अन्य कार्यों के साथ अपनी आय में वृद्धि करने का उनके पास ज्ञान व साधन अवश्य उपलब्ध हो। परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न विमर्शों में भी विषय विशेषज्ञों ने जीविका अर्जन के उपायों पर विशेष प्रकाश डाला है। समय-समय पर माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने भी उच्च शिक्षा में कौशल विकास एवं मानवीय मूल्यों के समावेश की अनुशंसाए की है। इन सब को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों में जीविका उपार्जन के व्यवहारिक पक्ष एवं मानवीय मूल्यों से संबंधित संस्कारों को पाठ्क्रम में समावेश करने के उपायों पर व्यापक विमर्श किया है। इस योजना में पहला कार्य स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों एवं उस विषय से संबंधित विशिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापकों को चिन्हित किया गया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री का सुझाव परिषद् को निरंतर प्राप्त होता रहा है।

सर्वप्रथम एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर इस परियोजना को आरंभ किया गया। इस संगोष्ठी में विमर्श के उपरांत मूलमंत्र के रूप में यह तय किया गया कि स्नातक स्तर के विषयों में आजीविका के दस-दस कार्य बिंदुओं को चिन्हित किया जाए। पहली संगोष्ठी में प्राप्त सुझाव के आलोक में दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत चयनित अध्यापकों को विषयों पर चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया । इस कार्यशाला में अध्यापकों ने पाठ्यक्रम में जीविका-उर्पाजन एवं जीवन मूल्यों के समावेश के महत्व पर चर्चा कर कुछ सुझाव परिषद् को सौंपे थे। इन सुझावों पर गहन विमर्श हेतु परिषद् कार्यालय में 04-05 फरवरी, 2019 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के चयनित 23 विषयों के 32 विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जा रहे

हर विषय में जीविका-उपार्जन के तत्व को समावेशित करने वाले 10 ऐसे कार्यों को चिन्हित किया गया जो युवा वर्ग के लिए आजीविका के माध्यम बन सकें।

बहरहाल, इस दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विषयों में जीविकोपार्जन के तत्व तलाशने के लिए मंथन का कार्य विषयों के प्रकृति के अनुसार 6 समूहों में बांट कर किया गया। इन समूहों की रचना इस प्रकार थी:

1. समूह 1 : प्रबंधन, वाणिज्य, पर्यटन
2. समूह 2: समाजशास्त्र, भूगोल , मनोविज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा
3. समूह 3: राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास
4. समूह 4: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, जनसंचार
5. समूह 5: भौतिकशास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, संगणक (कम्प्यूटर) विज्ञान
6. समूह 6: प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान

उपरोक्त समूहों में शामिल विद्वानों ने अंतर विषय संभावनाओं को तलाशा। इस दौरान विभिन्न विषयों के परस्पर सहयोग से हो सकने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। समूह चर्चा क बाद सामूहिक सत्र में सभी समूहों ने अपने-अपने विषयों में जीविकोपार्जन के दस-दस बिंदुओं को कार्यशाला में प्रस्तुत किया। इस कार्यशाला में हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के तत्कालिक अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं वर्तमान में प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी वी. उमा शंकर जी ने भी सहभागियों से चर्चा कर अपने सुझाव दिये। तत्पश्चात् हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा सभी विषयों में जीविकोपार्जन के दस-दस बिंदुओं एवं विद्वानों द्वारा दिये गए सुझावों को एक पुस्तिका के रूप में संकलित किया गया, जिसमें कार्य योजना के चिन्हित 21 विषय शामिल हैं। इस पुस्तिका में प्रत्येक विषय में शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य-योजना के साथ उद्देश्य, महत्व आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। पुस्तिका की सॉफ्टकॉपी प्रायोगिक अध्ययन के लिए प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों को प्रेषित की गई है। जिससे अध्यापक अपने पाठ्यक्रमों में इन जीविका उपार्जन के बिंदुओं को शामिल कर विद्यार्थियों को कार्य-अभ्यास करवा सकें। इस कार्य परियोजना में समय-समय पर सत्र के दौरान विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से प्रतिक्रिया लेने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे अधिक से अधिक व्यवहारिक एवं लाभप्रद बनाया जा सके। दूसरे चरण में शेष विषयों को चिन्हित करने की प्रक्रिया आरंभ किया जाना शेष है। अत: परिषद् का मत है कि प्रत्येक विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से यह पुस्तिका उपयोगी है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली युवा पीढ़ी इन

विषयों से जुड़े 10-10 कार्यों में से कोई 02 या 04 कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर जीविका-उपार्जन में सक्षम हो सकेंगे। अस्तु, परिषद् को अध्यापकों से विश्वास है कि वे अपने-अपने विषयों में निहित जीविकोपार्जन से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण देना प्रारंभ करेंगे ताकि हम समाज में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या के निकराकरण में सहायक बन सके।

28. परिषद् कार्यालय में पुस्तक, पत्रिका एवं समाचार-पत्र का प्रबंधन हेतु पुस्तकालय की स्थापना

परिषद् कार्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय में वर्तमान में हिंदी भाषा में अमर उजाला, दैनिक भास्कर और आंग्ल भाषा में टाइम्स ऑफ इंडिया, दी ट्रिब्यून समाचार-पत्र दैनिक रूप में एवं योजना, कुरूक्षेत्र, पॉलिटकिल एंड इकोनॉमिकली विकली पत्रिका सब्सक्राइब की गई है। पुस्तक क्रय करने का कार्य प्रगति में है।

29. सामान्य अधिनियम के मसौदे की समीक्षा के लिए अधिवक्ताओं की समिति का गठन

तीन विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की एक समिति गठित की गई। समिति ने सभी सरकार पोषित एवं सहायकता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य अधिनियम का मसौदा तैयार करने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद परिषद ने निर्मित अधिनियम के मसौदे की समीक्षा के लिए अधिवक्ताओं की समिति का गठन किया है। अधिवक्ताओं की समीक्षात्मक टिप्पणी आने के बाद मसौदा राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए सौंप दिया जायेगा।

30. अकादमिक परिषद में पूर्व विद्यार्थियों, पेशेवरों और अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करना

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालयों से अकादमिक परिषद और अध्ययन बोर्ड में पूर्व विद्यार्थियों, पेशेवरों और उद्योग के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया। इस बारे में माननीय राज्यपाल कुलाधिपति द्वारा अपेक्षित रपट राज्यपाल के सचिव को प्रस्तुत की गई है। इसकी प्रति माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ अनुलग्नक क्रमांक 03 (कुल पृष्ठ संख्या 02) पर उपलब्ध है।

31. नये महाविद्यालय स्थापित करने के लिए मानदंड सुझाने के लिए समिति का गठन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने नये महाविद्यालय स्थापित करने के लिए मानदंड सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था। प्राप्त रपट को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। समिति द्वारा सुझाए गए मानदंडों को अपनाने के लिए रपट की एक प्रति अनुलग्नक क्रमांक 04 (कुल पृष्ठ संख्या 11) पर उपलब्ध है।

32. उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना की समीक्षा

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2020-21 के लिए उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक योजना की समीक्षा की और फरवरी, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री को मसौदा प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि क्या इसे अद्यतन करने की आवश्यकता होगी। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को हरियाणा के संदर्भ में लागू किया जाना है। अत: इसके मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तदनुसार 2021-22 और उसके बाद की वार्षिक योजना का मसौदा तैयार किया जाना आवश्यक होगा। परिषद द्वारा इस संबंध में प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट संस्थान के निर्माण एवं हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए आयोजित 4 दिवसीय कार्यशाला से प्राप्त अनुशंसाओं को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा राज्य शिक्षक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है

33. शोध के आधुनिक क्षेत्रों का चयन

शोध के कुछ आधुनिक क्षेत्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार को सलाह भेजी गई। सहायता फीडबैक के मुताबिक सरकार द्वारा पोषित, सहायता प्राप्त और निजी विश्वविद्यालयों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।

34. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम (हरियाणा अधिनियम संख्या 4/2018) हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2018 को अधिसूचित किया गया है।तत्पश्चात् इममें संशोधन (अधिनियम संख्या

12/2020) सरकार द्वारा दिनांक 16.05.2020 को अधिसूचित किया गया। मूल अधिनियम अब संशोधनों के साथ माननीय सदस्यों के अवलोकन के लिए अनुलग्नक 01 (कुल पृष्ठ संख्या 07) पर रखा गया है।

35. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में नियुक्ति

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रकिया को पुर्ण करते हुए उपाध्यक्ष पद पर डॉ. केसी शर्मा को 08.06.2022 को परिषद में नवनियुक्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन और एफडी की सहमति से हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित नियमित पद सृजित किए गए हैं।

1. वरिष्ठ अकादमिक अन्वेषक एवं नियोजक (आचार्य के समकक्ष) = 02
2. अकादमिक अन्वेषक एवं नियोजक (सह आचार्य के समकक्ष) = 02
3. कनिष्ठ अकादमिक अन्वेषक एवं नियोजक (सहायक आचार्य के समकक्ष) = 04
4. निजी सचिव = 02
5. आशुलिपिक = 02
6. संपर्क और संचार सहायक = 01
7. डाटा एंट्री ऑपरेटर सह क्लर्क = 03
8. जूनियर प्रोग्रामर = 01
9. ग्रेड-04 = 04

उपरोक्त में से एक पद वरिष्ठ अकादमिक अन्वेषक एवं नियोजक (प्रतिनियुक्ति पर), कनिष्ठ अकादमिक अन्वेषक एवं नियोजक के दो पद (सीधी भर्ती द्वारा), समूह 'घ' (सीधी भर्ती द्वारा) के दो पद नियमानुसार प्रक्रिया को पालन करते हुए भरे गए हैं।

36. बजट का आवंटन

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान 4.10 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के बजट में 2022-23 के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

37. परिषद् कार्यालय के लिए स्थान आवंटित

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को तकनीकी शिक्षा सदन का द्वितीय तल (सभागार और सर्वर कक्ष को छोड़कर) उपलब्ध करा दिया गया है। इसे कार्य आवश्यकतानुसार उपयुक्त ढ़ंग से पुनर्निर्मित किया गया है। परिषद की आवश्यकता के अनुसार फिर से डिजाइन किया गया है। आवश्यकता अनुसार आवश्यक उपकरण, फर्नीचर भी मंगवाने की प्रक्रिया जारी है।

38. परिषद् में वाहन की खरीद

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सरकार के अनुमोदन उपरांत दो वाहन खरीदे हैं। इससे पूर्व एक वाहन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परिषद् के अध्यक्ष के लिए उपलब्ध करा दिया गया था।

39. स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास

परिषद ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग की मांग की है।

40. स्नातक स्तर पर महाविद्यालयों में जीविकोपार्जन एवं जीवन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देने बारे

विषय विशेषज्ञों, व्याख्याताओं और प्रधानाचार्यों के साथ परामर्शी बैठकों के परिणामस्वरूप, 21 विषयों में आजीविका, मूल्य आधारित बिंदुओं की पहचान की गई; पुस्तिका तैयार की गई है और इसे शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने के लिए कॉलेजों के साथ साझा किया गया है।

41. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के पास प्रक्रियाधीन विषय

परीक्षा प्रणाली में सुधार और पाठ्यक्रम को समकालीन और प्रासंगिक बनाना

यह एक सतत प्रक्रिया होने के कारण विश्वविद्यालयों को इस संबंध में एडवाइजरी भेजी गई गई।

(i) 5 विश्वविद्यालयों द्वारा पायलट के रूप में परीक्षण की मांग पर परीक्षा/परीक्षा का फ्लेक्सी मोड, कॉन्सेप्ट नोट अन्य विश्वविद्यालयों के साथ भी साझा किया गया।

(ii) सीखने का मिश्रित तरीका और उसके लिए चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा तदनुसार पाठ्यक्रम सामग्री का वर्गीकरण प्रक्रियाधीन है।

(iii) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्व-शिक्षण पाठ्यक्रम आदि- एसवीएसयू, पलवल को सौंपा गया। 13 महाविद्यालयों के लगभग 70 शिक्षकों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कवर किया गया है। इसके बाद कोर्सवेयर में सुधार एवं अद्यतन करते हुए कोर्सवेयर के माध्यम से सीखने के आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षकों को कवर करने की योजना है। प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के पास पड़ा है।

42. शोध में नवाचार के उपाय

यह विषय उच्च शिक्षा विभाग में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि हरियाणा राज्य उच्च परिषद ने प्रभावी क्षेत्रों में शोध करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ सिफारिशों को साझा किया है।

43. विभागों का एकीकरण

अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को देखते हुए उच्च शिक्षा का एकीकरण होना है। इस बारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गए निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया गया तथा यह विषय उच्च शिक्षा विभाग के पास विचाराधीन है।

44. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के लिए नियम और विनियम

परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी नई दिल्ली के प्रो विवेक कुमार, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत के कुलसचिव और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के परामर्शदाता की एक समिति नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए गठित किया गया था। समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तब इस विषय पर मुख्यमंत्री के तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव (अब पीएससीएम) के साथ चर्चा की गई थी, चर्चा अनुसार यह तय किया गया था कि नियम अलग से बनाए जाएं और राज्य सरकार से अधिसूचित किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि परिषद को न्यूनतम पदों पर भर्ती के प्रावधान को नियमों में शामिल कर अपने कामकाज के लिए नियमित पदों की नियुक्ति और वित्त विभाग की सहमति से इन्हें सृजित करना करना चाहिए। विभिन्न

परियोजनाओं के लिए अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, अन्यथा समय-समय पर खुले विज्ञापन आदि के माध्यम से आउटसोर्स/नियुक्त किया जाता है।

इस परिदृश्य में इस प्रकार तैयार किए गए नियमों को उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित विभिन्न आवश्यक नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव एफडी की सहमति से तैयार किया गया है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 22 के तहत विशेषज्ञों की नियुक्ति, अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और परिषद के कामकाज के लिए नियमों का भी मसौदा तैयार किया गया है और इसे परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा।

45. शिक्षा नीति के माध्यम से स्वच्छ और हरित हरियाणा को बढ़ावा देना

उच्च शिक्षा की सभी शाखाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पर्यावरण अध्ययन के अद्यतन शिक्षण के लिए गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रेषित पत्राचार में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को संदर्भित करते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य एक विश्व आबादी का विकास करना है जो पर्यावरण के बारे में चिंतित है। आबादी को पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्हें ज्ञान से अवगत कराया जाना चाहिए और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के मुद्दों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इसके आधार पर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को उच्च शिक्षा की सभी शाखाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पर्यावरण अध्ययन पर 6 महीने के कोर मॉड्यूल पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के निर्देश जारी किये हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने के लिए न्यायालय ने अपने निर्देश में यह भी प्रावधान किया कि पर्यावरण अध्ययन पर मॉड्यूल को पढ़ाने का कार्य उन शिक्षकों को सौंपा जाए जो यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं।

परिषद द्वारा मामले की जांच की गई। परिषद का सुविचारित विचार है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। दिए गए परिदृश्य में उच्च शिक्षा विभाग

यूजीसी के निर्देशों का समग्र रूप से पालन करने के लिए तुरंत कदम उठा सकता है। इसके लिए प्रथम चरण के रूप में नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है कि

(1) पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के योग्य शिक्षकों को ही पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का कार्य आवंटित किया जाये।

(2) तत्पश्चात् प्रत्येक महाविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान में व्याख्याता का एक पद नियमित आधार पर भरा जाये।

(3) चूंकि पदों के सृजन और नियमित शिक्षकों की तैनाती में समय लगेगा ऐसे समय तक जब तक पद सृजित और नियमित आधार पर भरे नहीं जाते, तब तक प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में योग्य शिक्षकों को एक्सटेंशन लेक्चरर /अतिथि संकाय के माध्यम से पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए शिक्षण कार्य सौंपा जा सकता है।

मामले को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। विभाग ने सूचित किया है कि मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

46. बाहरी विशेषज्ञों के लिए टीए/डीए/सहभागिता शुल्क आदि

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार परिषद के प्राथमिक कार्य प्रकृति में मुख्य रूप से अकादमिक हैं। इसके लिए परिषद परामर्श बैठकों, विचार-मंथन सत्रों, कार्यशालाओं का आयोजन करती रही है/ करती रहेगी।

परिषद के पुनर्गठन के अभाव में, कार्यालय यूजीसी की दिनांक 22.09.2017 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार दावों का निपटारा कर रहा है: -

“अधिकारी/गैर-आधिकारिक सदस्य रुपये के मानदेय के हकदार हैं। 3000 प्रति दिन प्रति बैठक अधिकतम रु. एक दिन में बैठकों की संख्या की परवाह किए बिना 5000 प्रति दिन। जहां तक टीए/डीए का संबंध है, इसका भुगतान चलनी में पात्रता के अनुसार या सेवानिवृत्ति से पहले जैसा भी मामला हो, किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव यह है कि परिषद् आवश्यकता पड़ने पर उनके ठहरने की व्यवस्था भी कर सकती है और कारणों को दर्ज करते हुए मामले के आधार पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकता है ताकि उपयोगी विचार-विमर्श के लिए विशेषज्ञों को आकर्षित किया जा सके।

47. हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम संख्या 4) में संशोधन कर परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता है। परिषद की दूसरी बैठक संशोधित अधिनियम के अनुसार परिषद के पुनर्गठन के बाद ही हो सकती है। राज्य सरकार को मसौदा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। यह विभाग द्वारा अधिसूचित है।

48. लघु समयावधि सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना को ध्यान में रखते हुए रोजगारोन्मुखी लघु अवधि प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों और परिषद द्वारा प्रस्तावित के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा है, इन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग के साथ साझा किया गया है। समिति के गठन, समिति की सिफारिशों और परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक की एक प्रति परिषद के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अनुलग्नक 05 (कुल पृष्ठ संख्या 07) पर रखा गया है।
पर रखी गई है।

49. वर्टिकल कोर्स में प्रवेश के लिए बी. वोक डिग्री की पात्रता

हरियाणा राज्य सरकार आयुष, स्वास्थ्य, खेल, तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन, कृषि जैसे अन्य विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों पर हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सलाह लेती रहती हैं और इसे प्राथमिकता के आधार पर दिया गया था।

परिषद् ने सरकारी महाविद्यालय परिसर में परमवीर चक्र योद्धाओं के चित्र प्रदर्शित करने वाले "हीरोज की दीवार" स्थापित करने के लिए कॉलेज के प्राचार्यों से अनुरोध किया।

परिषद ने संबद्ध महाविद्यालयों की प्रबंधन समिति/शासी निकाय के गठन की समीक्षा की और सुझाव दिया कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले 11 सदस्यों में से कम से कम स्नातक योग्यता रखने वाले 5 सदस्यों को नामांकन के लिए पात्र बनाया जाए। इसे विभाग से साझा किया गया।

दो मुद्दों पर विभाग के एक संदर्भ में परिषद- एक डिग्री कोर्स के समकक्ष बी.वोक डिग्री की मान्यता, जहां किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रोजगार के लिए पात्रता शर्त है, और दूसरा- पात्र

बी.वोक पास आउट करने के लिए। उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जहां प्रवेश योग्यता एक विशेष विषय की विशिष्ट आवश्यकता के बिना स्नातक की डिग्री है, निम्नानुसार सलाह दी गई: - "राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बी.वोक डिग्री को रोजगार के उद्देश्य के लिए डिग्री कोर्स के समकक्ष मान्यता दी जानी चाहिए, जहां किसी भी विषय में 'बैचलर डिग्री' रोजगार के लिए पात्रता की शर्त है। इसके लिए राज्य सरकार 'सीएस अधिकारी 0 सभी संबंधितों को निर्णय से अवगत करा सकते हैं।'
वर्टिकल कोर्स में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना विश्वविद्यालय के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आता है।" राज्य सरकार 16 निजी विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करने के प्रस्तावों को सलाह के लिए भेजा गया। प्रस्ताव की जांच की गई और इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए पाठ्यक्रमों को विभाग के पास भेज दिया गया।

50. सुरक्षित परिसर चेकलिस्ट

यूजीसी के दिशानिर्देशों और विनियमों के आधार पर परिषद ने महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लिए एक 'सुरक्षित परिसर चेकलिस्ट' तैयार की और इसे विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया।
परिषद् ने COVID-19 महामारी के शिक्षा के प्रबंधन बारे में पढ़ने वाले राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।
परिषद विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक मुद्दों पर विचार-विमर्श/विचार साझा करती रही है। इस संबंध में विशेष रूप आधुनिक विषय और एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली में विशेषज्ञता के क्षेत्र की पहचान, कर्मचारी कौशल मॉड्यूल को अपनाना, रोजगार सृजन के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उद्योग-अकादमिक संबंधों को महत्व देना आदि शामिल हैं।

51. राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण

हरियाणा सरकार प्रथम चरण में अनिवार्य रूप से भरे जाने वाले स्वीकृत रिक्त शिक्षण/गैर-शैक्षणिक बजटीय पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, जिसे सम्पन्न करके परिषद् की अनुशंसाओं पर सरकार ने आवश्यक स्वीकृतियां विश्वविद्यालय को जारी की दी।

परिषद् ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा साझा की गई वार्षिक मसौदा योजना 2020-21 की समीक्षा की। परिषद ने व्यापक परामर्श के बाद वार्षिक योजना की समीक्षा की और राज्य सरकार के साथ साझा की। यहां तक कि वार्षिक योजना 2021-22 के इनपुट भी प्रशासकीय सचिव के साथ साझा किए गए थे। 2022-23 की वार्षिक योजना का मसौदा विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने 29.05.2020 को "अकादमिक नेतृत्व की भूमिका" पर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसमें कुलपतियों, वरिष्ठ शिक्षाविदों ने भाग लिया। श्री मुकुल कानिटकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल ने प्रस्तुति दी जहां माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। परिषद् ने राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अकादमिक परिषद और अध्ययन बोर्ड में पूर्व छात्रों, पेशे, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया।

52. राज्य के विश्वविद्यालयों में फ्लेक्सी परीक्षा प्रणाली/मांग पर परीक्षा का प्रयोग

समय-समय पर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। महामारी COVID-19 ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कीं, जिनमें नवाचारों को तेज़ गति से लाना आवश्यक हो गया। शिक्षा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से सामाजिक दूरी को देखते हुए जिसका अक्षरश: पालन किया जाना आवश्यक था।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने कुलपतियों के साथ परामर्श बैठकों के माध्यम से मांग पर परीक्षा/परीक्षा के फ्लेक्सी मोड की अवधारणा पर विचार किया, जिसके अन्तर्गत छात्र किसी भी समय किसी भी विषय में उपस्थित हो सकता है और उस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की आपूर्ति प्रश्न बैंक स्थापित करके आयोजित किया जा सकता है।

मीडिया में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की गतिविधियों की कवरेज

स्वदेश

एमसीयू में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-भारतीय दृष्टि पर संगोष्ठी एवं पुस्तक 'संवाद का स्वराज' का विमोचन

बिना संवाद के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है : प्रो. कुठियाला

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

कोरोना महामारी ने बता दिया है कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। भोजन और प्रजनन के साथ ही संवाद भी मानव की बायोलॉजिकल आवश्यकता है। बिना संवाद के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने व्यक्त किए। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि की ओर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय दृष्टि विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।

इस अवसर पर उनकी पुस्तक संवाद का स्वराज का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी उपस्थित रहे और अध्यक्षता कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने की।



भारत की दृष्टि बहुत व्यापक : तिवारी

संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि सामान्य तौर पर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक अधिकारों तक सीमित करके देखते हैं। जबकि अभिव्यक्ति के प्रति भारत की दृष्टि बहुत व्यापक है। विश्व में भारत ही इकलौता देश है जहां अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की जाती है और उसकी स्वीकार्यता भी है। आत्मा भी ब्रह्म है और ज्ञान भी बह्हम। जो ब्रह्म मेरे भीतर है, वही तुम्हारे भीतर। भारत के लोगों ने इस अभिव्यक्ति को पेड़ों, नदियों और पर्वतों तक में किया है। श्री तिवारी ने कहा कि भारत में ऐसी घोषणाएं करने वालों के विरुद्ध कभी फतवा जारी नहीं किया गया। भारतीय दर्शन सब प्रकार के विचारों के पाचन का सामर्थ्य रखता है।

ये लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम में भोज मुक्त विवि के कुलपति प्रो. जयंत सोनवलकर, सांची विवि की कुलपति प्रो. नीरजा गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विवि के कुलपति प्रो. खेम सिंह डहेरिया, शुल्क विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. रवीन्द्र कान्हेरे, एलएनसीटी के कुलपति प्रो. नरेन्द्र थापक, आरकेडीएफ के कुलपति डॉ. एसके सोहनी एवं आईसेक्ट के प्रतिकुलपति प्रो. अमिताभ सक्सेना सहित अन्य विवि के कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य अधिकारीगण सहित शहर के गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

NEWS CLIPPING SERVICE FROM MCNUJC

संवाद बायोलॉजिकल जरूरत, इसके बिना जीवन संभव नहीं

एमसीयू में संगोष्ठी में प्रो. कुठियाला ने कहा

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

कोरोना महामारी ने बताया कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही मनुष्य की मूल जरूरत नहीं हैं। भोजन, प्रजनन के साथ संवाद भी बायोलॉजिकल आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है।

ये विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्ष प्रो. ब्रिज किशोर कुठियाला ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : भारतीय दृष्टि' विषय पर संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि रखे। उनकी पुस्तक 'संवाद का स्वराज' का विमोचन भी हुआ। राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी और कुलपति प्रो. केजी सुरेश मौजूद रहे। कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने जम्मू-कश्मीर के चुनावों की रिपोर्टिंग का उल्लेख कर कहा कि हमारी अभिव्यक्ति में भारत के लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। भोज विवि के कुलपति प्रो. जयंत सोनवलकर, सांची विवि की प्रो. नीरजा गुप्ता, अटल बिहारी हिंदी विवि के प्रो. खेम सिंह डहेरिया तथा शुल्क विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. रवींद्र कान्हेरे, एलएनसीटी के कुलपति प्रो. नरेंद्र थापक, आरकेडीएफ डॉ. एसके सोहनी, आईसेक्ट के प्रतिकुलपति प्रो. अमिताभ सक्सेना मौजूद रहे।

NEWS CLIPPING SERVICE FROM MCNUJC LIBRARY 'PEOPLES' 27 OCT 2021

मध्य स्वदेश
स्वदेश ग्वालियर समूह का भोपाल संस्करण

भोपाल - मध्य स्वदेश
27 Oct 2021

संवाद मानव की बायोलॉजिकल आवश्यकता: प्रो. कुठियाला

एमसीयू में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भारतीय दृष्टि' पर संगोष्ठी आयोजित

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल



कोरोना महामारी ने बता दिया है कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। भोजन और प्रजनन के साथ ही संवाद भी मानव की बायोलॉजिकल आवश्यकता है। बिना संवाद के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने व्यक्त किए। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भारतीय दृष्टि' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उनकी पुस्तक 'संवाद का स्वराज' का विमोचन भी किया गया।

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीय दृष्टि' पर अपने विचार रखते हुए प्रो. कुठियाला ने भारतीय वांग्मय के प्रसंग बताए। साथ ही कहा कि संवाद के प्रति भारतीय दृष्टि लोक कल्याण की है। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भारतीय दृष्टि में संवाद में अधिकार की भावना से अधिक मर्यादा की बात है। समाज को लाभ पहुँचाना ही वाणी का तप है। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि सामान्य [illegible] संवैधानिक अधिकारों तक सीमित करके देखते हैं। अभिव्यक्ति में भारत के लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। जबकि देखने में आता है कि जम्मू-कश्मीर का प्रकरण हो, कुलभूषण जाधव का प्रकरण हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने भारत के प्रतिकूल रिपोर्टिंग की। उन्होंने कहा कि हमें संवाद पर पश्चिम के दृष्टिकोण को पढ़ने के साथ ही भारत की संचार परंपरा का भी गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता एवं साहित्य में हमें भारतीय दृष्टि दिखाई देती है। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक व्याख्यान संवाद की भारतीय परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र एवं देश के हित में [illegible]

संगोष्ठी में विषय का प्रतिपादन विश्वविद्यालय के

हरिभूमि
रोहतक -सिरसा
13 Feb 2021

अभिनव प्रयास कलमकार व लेखा कार्यों प्रथम जीवित अभियान से जिला।

कर रहा था। समाचार में उपायुक्त ने नाथ डाइया तक पंजाब के खाजांच्या में हुए नाथ डाइया सहित 9 पदक प्राप्त किए।

प्राध्यापकों को लेना होगा विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प

ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाना आज की आवश्यकता

हरिभूमि न्यूज ▶▶सिरसा

प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने सीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है और भारत केंद्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता में संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत को नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की शुरूआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह बात हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही।



सिरसा। सीडीएलयू में सेमिनार का शुभारंभ करते प्रो. कुठियाला और वीसी अजमेर सिंह मलिक।

कुठियाला ने कहा कि उच्च शिक्षा परिषद् आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 बैठक राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरे बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बातें करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित प्राध्यापकों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना है। यह सिखाने की जिम्मेदारी प्राध्यापकों को लेना होगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, कर्मचारी और संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्राध्यापक उपस्थित थे।

विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अवसर उपलब्ध होने पर वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते आए है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि तोकाल के आधार सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा स्थापना वर्ष से ही उत्तीर्ण उत्तरा को लगा अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कराने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन तथा सहयोग किया है।

शिक्षा नीति से तैयार होंगे देश के लिए समर्पित व आत्मनिर्भर युवा : कुठियाला

जागरण संवाददाता, सिरसा : हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सिखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केंद्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। इ नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता से संभव हो सकता है। प्रो. कुठियाला शुक्रवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थित सभागार में आइक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।

आत्मनिर्भर बनने का किया है उल्लेख : हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में प्रो. कुठियाला ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार उन्हें सफल उद्यमियों से बातें करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।



प्रो. कुठियाला को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित करते कुलपति प्रो. अजमेर सिंह। ▶विज्ञप्ति

उन्होंने सभागार में उपस्थित प्राध्यापकों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना है। कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि विवि आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। विवि के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अवसर उपलब्ध होने पर वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते आये हैं और आगे भी करेंगे। कार्यक्रम में लाइफ साइंस की अधिष्ठाता प्रो. प्रियंका सिवाच को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय में कैसल्टेंसी सेल के निदेशक प्रो. दीपी वार्ने ने विषय की प्रस्तावना रखते हुए आत्मनिर्भरता की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की युवा कल्याण निदेशिका डा. मीनू नेहरा ने किया।

12 Feb. 2021

'ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला सिखाना आज की जरूरत'

चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आईक्यूएसी सेल की ओर से सेमिनार का आयोजन

महिला वैज्ञानिक दिवस पर सेमिनार

भास्कर न्यूज

आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रही सीडीओएलयू

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता में संभव हो सकता है। यह चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आईक्यूएसी सेल की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर बतौर मुख्यतिथि बोलते हुए प्रोफेसर कुठियाला ने कहा कि उच्च शिक्षा परिषद आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 फैकल्टी राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बाहरवीं के बाद माहविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार मार्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है।

दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बातें करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्राध्यापकों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना है। यह सिखाने की जिम्मेदारी प्राध्यापकों को लेना होगी।



सीडीओएलयू में आयोजित सेमिनार के दौरान संबोधित करती प्राध्यापिका।

भास्कर न्यूज सिरसा

चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के रसायन विभाग और टीडीएन साइंस कॉलेज एसोसिएशन के सौजन्य से चेटर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रसायन विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. गीता गठी ने बताया कि विद्यार्थियों को जागरूक करने तथा उनमें साइंटिफिक टैम्परामेंट की वृद्धि करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल वीक वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया।

करती रहती है। जिला जेल में बंद जयप्रकाश पूनिया मौजूद थे।

विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प लें : प्रो. कुठियाला



कार्यक्रम का शुभारंभ करते प्रो. कुठियाला।

सिरसा (स.न्यूज)। प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्म-निर्भरता से संभव हो सकता है। आत्म-निर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपरोक्त विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने चौ.दे. देवीलाल विश्व विद्यालय के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहें।

ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना आज की आवश्यकता: प्रो. कुठियाला

सिरसा सिरसा टुडे

प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता में संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपरोक्त विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर बतौर मुख्यतिथि बोलते हुए प्रोफेसर कुठियाला ने कहा की उच्च शिक्षा परिषद् आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 फैकल्टी राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बाहरवीं के बाद माहविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार मार्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बातें करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित प्राध्यापकों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना है। प्रो. कुठियाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल जिन के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वे लोक-लज्जा शब्द पर जोर देकर चर्चा करते थे। यह शब्द आज बहुत ही व्यापक है। आज विद्यार्थियों के अंदर लोक-लज्जा का मूल भाव पैदा कर दिया जाए तो यह हमारी सफलता होगी।

विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है: प्रोफेसर मलिक

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने की और के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन गत माह करवाया गया है। उन्होंने कहा की विद्यार्थी हमारे प्रथम स्टेक होल्डर्स है और उनको प्रत्येक प्रकार की शैक्षणिक सुविधाये प्रदान करने के लिये हम सभी वचन बद्ध है। मुख्य अतिथि का धन्यवाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ राकेश सक्सेना द्वारा किया गया। इस अवसर लाइफ साइंस की अधिष्ठाता प्रो. विनीता सिवाच को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी के निदेशक प्रोफेसर पंकज शर्मा ने मुख्य अतिथि का परिचय करवाया और विश्वविद्यालय में कमलरेमी सेल के निदेशक प्रो. डी.पी. वार्ने ने विषय की प्रस्तावना रखते हुए आत्मनिर्भरता की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की युवा कल्याण निदेशिका डॉ. मंजु चेना ने किया।



'सीखने-सिखाने की नीति पर कार्य करें प्राध्यापक'

16
12 Feb. 202



सिरसा में शुक्रवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए। निस

सिरसा (निस) : प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सिखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। ये विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर सीडीएलयू के कुलपति प्रो. अजमेर मलिक, कुलसचिव राकेश वधवा, अमित सांगवान, प्रो. दिलबाग सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सेमिनार

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने दी जानकारी

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी बनेंगे आत्मनिर्भर

माई सिरी रिपोर्टर



सेमिनार में प्रो. बीके कुठियाला को सम्मानित करते कुलपति प्रो. रंजेश्वर कुमार।

हिसार। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवा की सोच में परिवर्तन लाना होगा।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों के साथ तीन चरणों में संपर्क करना होगा। इन चरणों में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का सपना कैसे में समझाया जाएगा। प्रो. कुठियाला गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 'स्वावलंबी हिसार व आत्मनिर्भर भारत : विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर आयोजित सेमिनार को खतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रंजेश्वर कुमार ने कहा कि भारतीय के रूप में हमें अपनी भूमिका ऐसे तैयार करनी है कि हम भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य तैयार करें। इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका निभानी होगी। विशिष्ट वक्ता कैप्टन राजेंद्र प्रताप सिंह ने इंटीग्रेटिड एजुकेशन हब की भविष्य की व्यवस्थाओं और संभावनाओं के बारे में बताया।

हमारे उत्पादन विश्व के अन्य उत्पादों से बेहतर हों : मुख्य वक्ता प्रो. एसके बिश्नोई ने कहा कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि जो हम बनाएं वह अपना हो, बल्कि यह है कि हमारे उत्पाद, क्वालिटी, गुणवत्ता और अन्य दृष्टियों से विश्व के अन्य उत्पादों से बेहतर हों। उन्होंने देशों और योजनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि तकनीक से समाज की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय इस मामले में मार्गदर्शक हो सकते हैं। कुलसचिव डॉ. अवनीश यादव ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बनें और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम संयोजक प्रो. संदीप रस्तोगी ने कहा कि आत्मनिर्भर सोच से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत वहां का मानव संसाधन है। शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को समझने की बजाए समझने की आवश्यकता है।

युवाओं की सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत : कुठियाला

12 Feb 2021

जागरण संवाददाता हिसार : हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. भीम कुठियाला ने कहा है कि कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवाओं की सोच में परिवर्तन लाना होगा। युवा को समझना होगा कि उसे नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। प्रो. कुठियाला गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित स्वावलंबी हिसार व आत्मनिर्भर भारत : विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।



गुजरी में सेमिनार को संबोधित करते मुख्यातिथि प्रो. भीम कुठियाला। • हिप्रेस

सेमिनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की। टास्क फोर्स कमेटी के फाउंडर सदस्य तथा ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सदस्य कैप्टन राजेश प्रताप सिंह विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. एनके त्रिपाठी मुख्य वक्ता तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. अवनेश कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा थे। इस सेमीनार में विश्वविद्यालय के शिक्षक डा. पंकज खटक द्वारा कृत्रिम हाथ से सम्बंधित किए जा रहे नए उत्पाद के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यातिथि प्रो. कुठियाला ने कहा कि किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की भूमिका सर्वोपरि होती है। समाज शिक्षक पर सर्वाधिक विश्वास करता है। यही कारण है कि शिक्षक के पास बिना किसी चिंता के अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। शिक्षक शिक्षित, ज्ञानवान व ज्ञान के प्रचार व प्रसार का वाहक होता है। शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से इस प्रकार तैयार करें कि वो वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके।

उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा हर क्षेत्र में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। भारत के युवा के पास जितने मौके हैं, दुनिया के किसी अन्य युवा के पास इस प्रकार के मौके नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों के साथ तीन चरणों में सम्पर्क करना होगा। इन चरणों में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के सभी मुख्य बिन्दू समझाए जाएंगे।

जीजेयू में स्वावलंबी हिसार और आत्मनिर्भर भारत में विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर सेमिनार का किया आयोजन

भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बनाएं योग्य : प्रो. टंकेश्वर

कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि कोविड-19 के बाद हमें नई योजना की जरूरत है। भारतीय के रूप में हमें अपनी भूमिका ऐसे तैयार करनी है कि हम भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतियोगिता के योग्य तैयार करें। इसमें विश्वविद्यालयों की अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से ही देश चलता है। आने वाले समय में भारत में भी विश्वविद्यालयों की भूमिका बदलनी चाहिए। विशिष्ट वक्ता कैप्टन राजेश प्रताप सिंह ने हिसार हवाई अड्डे तथा यहां से सम्बंधित हवाई यात्राओं का पूर्ण विवरण दिया।

उन्होंने इंटिग्रेटिड ऑपरेशन हब का थ्री डि प्रस्तुत किया तथा बताया कि किस प्रकार और किन चरणों से गुजरकर हिसार की हवाई यात्रा का सपना पूरा हो सका है और भविष्य में यहां किस प्रकार की व्यवस्थाएं और सम्भावनाएं है।

ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना आज की आवश्यकता: प्रो. कुठियाला

पल पल न्यूज: सिरसा, 12 फरवरी। प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने-सीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केंद्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता में सहायक हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहले चार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की सूत्र भात मानसिकता के बदलने से होते हैं और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपरोक्त विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. भीम किशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सहायार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् और चौधरी देवीलाल



विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर बतौर मुख्यातिथि बोलते हुए प्रोफेसर कुठियाला ने कहा की उच्च शिक्षा परिषद् आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 बैठक राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बात करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जाना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बात करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित प्राध्यापकों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना है। यह सिखाने की जिम्मेदारी प्राध्यापकों को लेना होगी। यह व्यक्तिगत रूप से भाव जगाने से संभव हो सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बजमेर सिंह मलिक ने की और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अवसर उपलब्ध होने पर वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते आये हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि का धन्यवाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ राकेश सहरावत द्वारा किया गया। इस अवसर लाइफ साइंस की अधिष्ठाता प्रो. प्रियंका सिवाच को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी के निदेशक प्रोफेसर पंकज शर्मा ने मुख्य अतिथि का परिचय करवाया और विश्वविद्यालय में कम्प्टरेंसी सेल के निदेशक प्रो. डी.पी. चार्ल ने विषय की प्रस्तावना रखते हुए आत्मनिर्भरता की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की युवा कल्याण निदेशिका डॉ. मंजू नेहरा ने किया । इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, कर्मचारी और सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्राध्यापक उपस्थित थे।

जीवन जीने की कला सिखाना भी आज की आवश्यकता : कुठियाला

भाई सिटी रिपोर्टर

सीडीएलयू के सभागार में आईक्यूएसी सेल ने आयोजित किया सेमिनार

सिरसा। प्राध्यापकों को पढ़ने-पढ़ाने की जगह सीखने सिखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केंद्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। ये विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. भीम किशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता में संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपरोक्त विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर बतौर मुख्यातिथि प्रोफेसर कुठियाला ने कहा कि उच्च शिक्षा परिषद आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 बैठकें राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से बात करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

विवि में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार आज

जासं, सिरसा : सीडीएलयू स्थित सेमिनार हॉल में वीरवार को केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद व विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। विवि के आइक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे जबकि सीडीएलयू के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक अध्यक्षता करेंगे।

सीडीएलयू में आज होगा सेमिनार, तैयारियां शुरू

भास्कर न्यूज | सिरसा

केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन गुरुवार को किया जाएगा।

वीसी प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

सीडीएलयू के आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित इस सेमिनार में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे जबकि सीडीएलयू के वीसी प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सेमिनार में विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों सहित विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्राध्यापक भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी टीचर्स का अहम योगदान है और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद प्रदेश भर में इस संबंध में सेमिनारों का आयोजन करने जा रही है।

आत्मनिर्भर योजना के तहत सेमिनार आज

सिरसा। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन 11 फरवरी को विश्वविद्यालय के सभागार में किया जाएगा। विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित इस सेमिनार में हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे जबकि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना जरूरीः प्रो. कुठियाला



सिरसा (निस)। प्राध्यापकों को पढ़ने पढ़ाने की जगह सीखने सिखलाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह बात हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृजकिशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार में प्रतिभागियों से कही। उन्होंने कहा कि यह संकल्प आत्मनिर्भरता से संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा परिषद आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 बैठक राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों व अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने दस जमा दो के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्यापकों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से वार्ता करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित प्राध्यापकों से आग्रह किया कि ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखलाना है। यह जिम्मेदारी प्राध्याापकों को लेना होगी।

वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देविवि के वाइस चांसलर प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि उनका विवि आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अवसर उपलब्ध होने पर वे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते आए हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा स्नातक स्तर से ही उद्योग जगत की मांग अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करवाने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन गत माह करवाया गया है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि का धन्यवाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राकेश बधवा द्वारा किया गया। इस अवसर लाइफ साइंस की अधिष्ठाता प्रो. प्रियंका सिवाच को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आईक्यूएसी के निदेशक प्रोफेसर पंकज शर्मा, प्रो. डी.पी. वार्ने, डॉ. मंजू नेहरा सहित अनेक प्राध्यापक मौजूद थे।

श्रीविश्वकर्मा विश्वविद्यालय में ई-अध्ययन की शुरूआत 16 Feb 2021



निजी संवाददाता — चंडीगढ़

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दिन-प्रतिदिन शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सयुंक्त तत्वाधान में ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए ई-अध्ययन प्लेटफॉर्म 'सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग'की शुरूआत की जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला शामिल हुए। इस दौरान मुख्यअतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि ई-अध्ययन के द्वारा निपुण शिक्षकश्शिक्षाविद डिजिटल माध्यम से पढ़ने व सीखने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञानवर्धन करेंगे। शिक्षक स्वयं को शैक्षणिक रूप से ज्यादा मजबूत करेंगे, थ्योरी शिक्षण के साथ-साथ उनके व्यवहारिक पक्ष में अच्छे प्रकार के प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण के विभिन्न विधियों को जानकर व्यवहार में लाएंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयु के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि शिक्षक को हमेशा व्यवसायी एवं तकनीकी ज्ञान सीखने में तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कुशलता पूर्वक जीवन के विभिन्न पड़ाव के लिए समयानुसार और आवश्यकतानुसार निपुण करना चाहिए। कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार और व्यवसायी तकनीकी में कुशल बनाना एवं भविष्य में चुनौतियों से निपटने एवं बेहतर शिक्षण के लिए तैयार करना। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित डीन एकेडमिक डा. एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को आधुनिक रूप से पूर्ण मजबूत होने के साथ.साथ शिक्षण के विभिन्न पक्षों को समय-समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन कोर्स पूर्ण करने में 40 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार से सात इकाई बनाए हुए हैंए जो शिक्षक के ज्ञानवर्धान को विभिन्न पक्षों से सुदृढ़ करेगा।

रीयल संवाद नई दिल्ली, मंगलवार, 16 फरवरी 2021 देश संवाद

ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शुरू किया ई-अध्ययन



श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दिन-प्रतिदिन शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए 'ई-अध्ययन प्लेटफॉर्म' 'सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग' की शुरूआत की जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्यअतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला शामिल हुए। इस दौरान मुख्यअतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि ई-अध्ययन के द्वारा निपुण शिक्षकश्शिक्षाविद डिजिटल माध्यम से पढ़ने व सीखने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञानवर्धन करेंगे। शिक्षक स्वयं को शैक्षणिक रूप से ज्यादा मजबूत करेंगे, थ्योरी शिक्षण के साथ-साथ उनके व्यवहारिक पक्ष में अच्छे प्रकार के प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण के विभिन्न विधियों को जानकर व्यवहार में लाएंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयु के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि शिक्षक को हमेशा व्यवसायी एवं तकनीकी ज्ञान सीखने में तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कुशलता पूर्वक जीवन के विभिन्न पड़ाव के लिए समयानुसार और आवश्यकतानुसार निपुण करना चाहिए। कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार और व्यवसायी तकनीकी में कुशल बनाना एवं भविष्य में चुनौतियों से निपटने एवं बेहतर शिक्षण के लिए तैयार करना। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित डीन एकेडमिक डा. एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को आधुनिक रूप से पूर्ण मजबूत होने के साथ.साथ शिक्षण के विभिन्न पक्षों को समय-समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन कोर्स पूर्ण करने में 40 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार से सात इकाई बनाए हुए हैं, जो शिक्षक के ज्ञानवर्धान को विभिन्न पक्षों से सुदृढ़ करेगा। इस कोर्स को कोर्डिनेटर डॉ. अंशु भारद्वाज एवं उनकी टीम डॉ रविन्द्र, श्रीमती चंचल भारद्वाज, डॉ रामकुमार, डॉ तनीष, डॉ मोहित एवं तकनीकी टीम श्री प्रवीण कुमार, डॉ विश्विजीत की कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भूमिका और सहयोग रहा।

ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शुरू किया ई-अध्ययन

स्पूतन इंडिया /ब्यूरो

चण्डीगढ़। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दिन-प्रतिदिन शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए 'ई-अध्ययन प्लेटफॉर्म' 'सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग' की शुरूआत की जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्यअतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला शामिल हुए। इस दौरान मुख्यअतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि ई-अध्ययन के द्वारा निपुण शिक्षकश्शिक्षाविद डिजिटल माध्यम से पढ़ने व सीखने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञानवर्धन करेंगे। शिक्षक स्वयं को शैक्षणिक रूप से ज्यादा मजबूत करेंगे, थ्योरी शिक्षण के साथ-साथ उनके व्यवहारिक पक्ष में अच्छे प्रकार के प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण के विभिन्न विधियों को जानकर व्यवहार में लाएंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयु के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि शिक्षक को हमेशा व्यवसायी एवं तकनीकी ज्ञान सीखने में तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कुशलता पूर्वक जीवन के विभिन्न पड़ाव के लिए समयानुसार और आवश्यकतानुसार निपुण करना चाहिए। कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार और व्यवसायी तकनीकी में कुशल बनाना एवं भविष्य में चुनौतियों से निपटने एवं बेहतर शिक्षण के लिए तैयार करना। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित डीन एकेडमिक डा. एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को आधुनिक रूप से पूर्ण मजबूत होने के साथ-साथ शिक्षण के विभिन्न पक्षों को समय-समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन कोर्स पूर्ण करने में 40 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार से सात इकाई बनाए हुए हैं, जो शिक्षक के ज्ञानवर्धान को विभिन्न पक्षों से सुदृढ़ करेगा। इस कोर्स को कोर्डिनेटर डॉ अंशु भारद्वाज एवं उनकी टीम डॉ रविन्द्र, श्रीमती चंचल भारद्वाज, डॉ रामकुमार, डॉ तनीष, डॉ मोहित एवं तकनीकी टीम श्री प्रवीण कुमार, डॉ विश्विजीत की कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भूमिका और सहयोग रहा।

16 Feb. 2021

ज्ञान के साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाना आज की आवश्यकता: प्रो. कुठियाला

सिरसा (विवेचक) प्राध्यापकों को पढ़ने ढ्ढपढ़ाने की जगह सीखने ढ्ढसीखाने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत केन्द्रित शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध करा रही है। नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण कार्य आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करना है। विद्यार्थियों के जीवन को संवारने का संकल्प प्राध्यापकों को लेना होगा। यह संकल्प आत्मनिर्भरता से संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाने का उल्लेख पहली बार भारत की नवीन शिक्षा नीति में किया गया है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत मानसिकता के बदलने से होती है और इस कार्य में प्राध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपरोक्त विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के सभागार में आईक्यूएसी सेल द्वारा आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता में अध्यापक की भूमिका विषय पर बतौर मुख्यातिथि बोलते हुए प्रोफेसर कुठियाला ने कहा की उच्च शिक्षा परिषद् आत्मनिर्भरता की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रयास में अब तक 17 बैठक राज्य के विद्यार्थियों, प्राध्याकपकों और अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने बारहवीं के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनसे प्राध्याप्कों को तीन बार संपर्क करना है। पहली बार के संपर्क में विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देना है। दूसरी बार में आत्मनिर्भरता के उपायों को बताना है और तीसरी बार में उन्हें सफल उद्यमियों से वार्ता करवानी है ताकि युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शुरू किया ई-अध्ययन

चंडीगढ़(आपका फैसला)। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दिन-प्रतिदिन शैक्षणिक अध्ययन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए 'ई-अध्ययन प्लेटफार्म' 'सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग' की शुरुआत की जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्यअतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला शामिल हुए। इस दौरान मुख्यअतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि ई-अध्ययन के द्वारा निपुण शिक्षक/शिक्षिका डिजिटल माध्यम से पढ़ने व सीखने के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञानवर्धन करेंगे। शिक्षक स्वयं को शैक्षणिक रूप से ज्यादा मजबूत करेंगे, स्थायी शिक्षण के साथ-साथ उनके व्यवसायिक पक्ष में अच्छे प्रकार के प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण के विभिन्न विधियों की जानकर व्यवहार में लाएंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयू के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि शिक्षक को हमेशा व्यवसायी एवं तकनीकी ज्ञान सीखने में तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कुशलता पूर्वक जीवन के विभिन्न पड़ाव के लिए समयानुसार और आवश्यकतानुसार निपुण करना चाहिए। कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार और व्यवसायी तकनीकी में कुशल बनाना एवं भविष्य में चुनौतियों से निपटने एवं बेहतर शिक्षण के लिए तैयार करना। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित डीन एकेडमिक डॉ एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को आधुनिक रूप से पूर्ण मजबूत होने के साथ-साथ शिक्षण के विभिन्न पक्षों को समय-समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह ऑनलाइन कोर्स पूर्ण करने में 40 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार से सात इकाई बनाए हुए हैं, जो शिक्षक के ज्ञानवर्धन को विभिन्न पक्षों से मजबूत करेगा। इस कोर्स की कोर्डिनेटर डॉ अंजु भारद्वाज एवं उनकी टीम डॉ रविन्द्र, चंचल भारद्वाज, डॉ राजकुमार, डॉ दलीप, डॉ मोहित एवं तकनीकी टीम की प्रवीण कुमार, डॉ निशिकेतन की कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भूमिका रही।

एसवीएसयू ने शुरू किया 40 घंटों का डिजिटल लर्निंग को

गुरुग्राम। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए ई-अध्ययन की शुरुआत की है। इस कोर्स से शिक्षकों को नवाचार और व्यवसायी तकनीकी में कुशल बनाया जाएगा। साथ ही वे भविष्य में बेहतर शिक्षण के लिए तै रहेंगे। इस कोर्स को पूरा करने के लिए 40 घंटे की अ निर्धारित की गई है। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिष के संयुक्त तत्वावधान में इस स्व अध्ययन डिजिटल ल कोर्स शुरू किया गया है। इसके उद्घाटन समारोह में मु अतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला पहुंचे। ब्यूरो

ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने शुरू किया ई-अध्ययन









16 Feb. 2024







प्रो. बी.के. कुठियाला ने कहा-युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है

हिसार | कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवा की सोच में परिवर्तन लाना होगा। युवा को समझाना होगा कि उसे नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। कुछ ऐसे ही शब्दों से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने।

दरअसल, जीजेयू तथा हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 'स्वावलम्बी हिसार व आत्मनिर्भर भारत, विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर सेमीनार हुआ। सेमीनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की। टास्क फोर्स कमेटी के फाउंडर सदस्य तथा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटेग्रेटिड एविएशन हब के सदस्य कैप्टन राजेश प्रताप सिंह विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित



थे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. एनके बिश्नोई मुख्य वक्ता तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अवनीश वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा थे। मुख्य वक्ता प्रो. एन.के. बिश्नोई और कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. विकास वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। संचालन शिक्षिका डॉ. फल्गवी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के सह-समन्वयक डॉ. हरदेव सिंह उपस्थित रहे।



26 Feb. 2021

दस दिवसीय ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग का हुआ समापन



ह्यूमन इंडिया/ब्यूरो

पलवल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चल रहे दस दिवसीय ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। एसवीएसयू एवं हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सयुंक्त तत्वाधान में इस 'ई-अध्ययन प्लेटफॉर्म' 'सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग' की शुरुआत हुई जिसमें प्रांत के 13 अलग-अलग उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों ने भाग लिया एवं डिजिटल टीचिंग के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से अध्ययन किया। यह ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग कार्यक्रम उच्च शिक्षा में समकालीन समय की मांग को देखते हुए सात विभिन्न मॉडयूल में सम्पन करवाया गया। समापन समारोह में मुख्यअतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला शामिल हुए एवं सम्मानित अतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में सलाहकार श्रीमान ए के अग्निहोत्री जी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यअतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि कोविड-19 ने हमें चुनौतिया प्रदान की लेकिन अवसर भी बहुत दिए। इसी दिशा में ऑनलाइन अध्ययन महत्पूर्ण कड़ी के रूप में आया है। इसी में यह ऑनलाइन टीचिंग महत्वपूर्ण टूल साबित होगा। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयु के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि केवल तकनीकी वर्ग ही नहीं अपितु सभी पाठयक्रमों के शिक्षक अपनी शिक्षण शैली में इस ई अध्ययन प्रणाली को शामिल कर सकते हैं। डीन एकेडमिक डॉ एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग में मजबुत होना चाहिए। प्रोग्राम कॉर्डिनेटर डॉ अंशु भारद्वाज एवं उनकी टीम डॉ रविन्द्र, श्रीमती चंचल भारद्वाज, डॉ राजकुमार, डॉ दलीप, डॉ मोहित एवं तकनीकी टीम श्री प्रवीण कुमार, डॉ निखिलेश की कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भूमिका और सहयोग रहा।

दस दिवसीय ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग का हुआ समापन

वेलकम इंडिया

होडल(रतन सिंह)। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चल रहे दस दिवसीय ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। एसवीएसयू एवं हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सयुंक्त तत्वाधान में इस ई-अध्ययन प्लेटफॉर्म सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग की शुरूआत हुई जिसमें प्रांत के 13 अलग-अलग उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों ने भाग लिया एवं डिजिटल टीचिंग के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से अध्ययन किया। यह ई अध्ययन ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग कार्यक्रम उच्च शिक्षा में समकालीन समय की मांग को देखते हुए सात विभिन्न मॉडयूल में सम्पन करवाया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बीके कुठियाला शामिल हुए एवं सम्मानित अतिथि के तौर पर हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में सलाहकार श्रीमान ए के अग्निहोत्री जी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रो बीके कुठियाला ने कहा कि कोविड-19 ने हमें चुनौतिया प्रदान की लेकिन अवसर भी बहुत दिए। इसी दिशा में ऑनलाइन अध्ययन महत्पूर्ण कड़ी के रूप में आया है। इसी में यह ऑनलाइन टीचिंग महत्वपूर्ण टूल साबित होगा। विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसवीएसयु के कुलपति श्री राज नेहरु ने कहा कि केवल तकनीकी वर्ग ही नहीं अपितु सभी पाठयक्रमों के शिक्षक अपनी शिक्षण शैली में इस ई अध्ययन प्रणाली को शामिल कर सकते हैं। डीन एकेडमिक डॉ एस सरकार ने कहा कि शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग में मजबुत होना चाहिए। प्रोग्राम कॉर्डिनेटर डॉ अंशु भारद्वाज एवं उनकी टीम डॉ रविन्द्र, चंचल भारद्वाज, डॉ राजकुमार, डॉ. दलीप, डॉ मोहित एवं तकनीकी टीम प्रवीण कुमार, डॉ निखिलेश की कार्यक्रम के दौरान सक्रिय भूमिका और सहयोग रहा।

दैनिक जागरण हिसार, 27 फरवरी, 2021

नई शिक्षा नीति साबित होगी मील का पत्थर : कुठियाला

जागरण संवाददाता, सिरसा

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल व भारतीय शिक्षण मंडल एवं नीति आयोग के तत्वाधान में वेबिनार आयोजित किया गया। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करने में अध्यापक की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्यअतिथि राज्य उच्च शिक्षा के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में शैक्षणिक संस्थान व अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह नीति विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

विषयों का चयन आवश्यकता के अनुरूप करना होगा

मुख्यातिथि कुठियाला ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने विषयों को चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति को राष्ट्र के विकास का प्रतीक बताया और कहा कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ संस्था तथा राष्ट्र का विकास सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि इस नीति के क्रियान्वयन में अध्यापकों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके विद्यार्थियों को [illegible] होगा ताकि विद्यार्थी रोजगार लेने कि बजाए रोजगार देने की स्थिति में आ सके और नये नये उद्यम स्थापित करें।

व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी

अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने की और कहा कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण स्थापित करके विद्यार्थियों को न केवल कितबी ज्ञान बल्कि व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना भी शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति के विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने अध्यापकों से अनुरोध किया कि वे विद्यार्थियों को पहले सिखने के लिए प्रेरित करें उसके बाद नवीनतम ज्ञान से उन्हें अवगत करवाए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं के विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। चौ. बी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी के कुलसचिव डा. जितेन्द्र भारद्वाज ने शिक्षा के सुधार के लिए भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा उठाई गई विभिन्न पहलू कदमियों के बारे में अवगत करवाया। नई शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के लेकर उच्चतर शिक्षा तक के स्तर को सुधारने पर जोर देती है और आज समय कि मांग है कि पाश्चात्य मॉडलों को छोड़कर भारतीय मॉडलो और सिद्धांतो की खोज कि जाए। इस अवसर पर नवीन शिक्षा नीति के ऊपर मुकुल कानीतकर की यूटयूब वीडियो भी प्रतिभागियों को दिखाई गई और विविध विषयों के ऊपर चर्चा के लिए आगामी अलग सेशन चलाए गए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. राकेश वधवा, शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठाता प्रो. सुरेश गहलावत, प्रो. पंकज व प्रो. डीपी वार्ने मौजूद रहे।

25 Feb. 2021

दैनिक भास्कर

1

डीएन कॉलेज में एग्जिबिशन लगा नेताजी के बारे में बताया, 25 फरवरी से 3 मार्च तक लगेगा

सात दिवसीय प्रदर्शनी का प्रो. बीके कुठियाला और पूर्व मंत्री हरिसिंह सैनी ने किया उद्घाटन

भास्कर न्यूज | हिसार

दयानंद कॉलेज के इतिहास विभाग की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सात दिवसीय प्रदर्शनी 25 फरवरी से 3 मार्च तक कॉलेज में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यअतिथि के रूप में हरियाणा शिक्षा उच्चतर शिक्षा परिषद् के चेयरपर्सन प्रो. बीके कुठियाला ने ऑनलाइन के माध्यम से तथा पूर्व मंत्री हरिसिंह सैनी व आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के उपप्रधान ने किया।

अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को पुष्प अर्पित करने के बाद कॉलेज द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों का विवरण अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया



डीएन कॉलेज में लगे एग्जिबिशन में जानकारी लेते लोग।

तथा उन्होंने नेताजी की प्रतिभा, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान व समर्पण को रेखांकित करते हुए बताया कि उन्होंने देश सेवा के लिए किस तरह से आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने किस तरह से विभिन्न देशों की यात्रा के बाद जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रो. बीके कुठियाला ने ऑनलाइन संबोधन दिया। मुख्यातिथि चौधरी हरिसिंह सैनी ने नेताजी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें नेताजी के आदर्शों पर चलकर देश के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देना है। प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने इस आयोजन के लिए इतिहास विभाग को बधाई दी।

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में केस दर्ज

दो भाई सहित पांच पर मारपीट, छेड़छाड़ और अपशब्द बोलने का आरोप लगाया

S.D. MODERN Pl
Bhagat Singh Road,
(A Co-Educational CBSE Affiliat
REQU

प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता-प्रो. कुठियाला

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 25 फरवरी : दयानन्द महाविद्यालय, हिसार के इतिहास विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयन्ती के अवसर पर आज से 3 मार्च तक चलने वाली सात दिवसीय प्रदर्शनी का महाविद्यालय में उपचुनाव आज मुख्य अतिथि में प्रोफेसर श्री.के. कुठियाला, चेयरपर्सन, हरियाणा शिक्षा उच्चतर शिक्षा समिति ने ऑनलाइन के माध्यम से तथा चौधरी हरिसिंह सैनी, पूर्व मन्त्री, हरियाणा सरकार व आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के उपप्रधान ने किया। अतिथियों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र को पुष्प अर्पित करने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों का विवरण अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उन्होंने नेताजी की प्रतिभा, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान व समर्पण को रेखांकित करते हुए बताया कि उन्होंने देश सेवा के लिए किस तरह से आई.सी.एस. के पद से इस्तीफा दे दिया था तथा उन्होंने किस तरह से विभिन्न देशों की यात्रा के उपरांत जापान में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। समारोह के मुख्यअतिथि तथा मुख्यवक्ता प्रोफेसर श्री.के. कुठियाला ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारत के इतिहास की ये गाथाएं हमारे सामने हैं जिसमें एक गाथा लोककथाओं व कथाओं में मिलती है जो सम्पन्न एवं समृद्धशाली भारत की परिकल्पना है तथा दूसरी गाथा यह है कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, जिसे बाहर के लोगों ने आकर बनाया तथा बसाया था। आज स्कूलों तथा कॉलेजों में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है उसमें नेताजी की अनुपस्थिति क्यों है जबकि आज के युवा को यह समझने की उत्सुकता है कि नेताजी ने देश की आजादी के लिए अपने आराम एवं सुखी जीवन का त्याग क्यों किया? क्या आज हम अपने पुत्र पौत्रों से "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का भाव पैदा कर सकते है? आज हमें सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलकर हमारे देश की उत्कृष्ट संस्कृति एवं इतिहास को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुख्यअतिथि चौधरी हरिसिंह सैनी ने अपने सम्बोधन में नेताजी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें नेताजी के आदर्शों पर चलकर देश के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देना है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने इस ज्ञानवर्धक आयोजन के लिए इतिहास विभाग को बधाई दी।



मुख्यअतिथि का परिचय समारोह में उपस्थित अतिथियों से करवाया। महाविद्यालय के विद्यार्थी शौकांत ने नेताजी के जीवन पर आधारित रागिनी सुनाकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। महाविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर परिवृ चक्रधर एवं डी.ए.वी. प्रबन्धक समिति के सदस्य डी.देवेन्द्र गुप्ता तथा प्रमोद लाम्बा के अतिरिक्त पंचकर्म योग संस्थान के उपाध्यक्ष श्री ज्ञानचन्द संसद उपस्थित रहे। मंच का संचालन डॉ. सुदर्शन शर्मा तथा डॉ. रश्मी चगल्ल ने किया। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आगंतुक सभी प्रबन्धकों व विद्यार्थियों का धन्यवाद किया।

25 Feb. 2021

नेताजी के आदर्श समझें युवा : प्रो. कुठियाला

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और त्याग को समझने के लिए प्रदर्शनी शुरू

माई सिटी रिपोर्टर

हिसार। दयानंद महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में सात दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ हरियाणा उच्चतर शिक्षा समिति के चेयरमैन प्रो. भीके कुठियाला और पूर्व मंत्री एवं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान हरिसिंह सैनी ने किया।

मुख्य अतिथि प्रो. भीके कुठियाला ने कहा कि भारत के संपन्न और समृद्ध इतिहास की एक गाथा लोकगीतों व कथाओं में मिलती है। दूसरी गाथा यह है कि भारत एक बिखरा हुआ देश था, जिसे बाहर के लोगों ने आकर बनाया और बसाया था। आज के युवा को यह समझने की जरूरत है कि नेताजी ने देश की आजादी के लिए अपने आदर्शों एवं सुंदर जीवन का त्याग क्यों किया? आज हमें सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलकर हमारे देश की प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।



कार्यक्रम में उपस्थित स्टाफ और अन्य।

पूर्व मंत्री चौधरी हरिसिंह सैनी ने कहा कि हमें नेताजी के आदर्शों पर चलकर देश के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देना है। प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने आयोजन के लिए इतिहास विभाग को बधाई दी। महाविद्यालय के विद्यार्थी श्रीकांत ने नेताजी के जीवन पर आधारित रागिनी सुनाकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। वहीं, अतिथियों ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों का विवरण अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिथियों ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा के लिए किस तरह से आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा के उपरांत जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इस दौरान देवेंद्र उप्पल, प्रमोद लांबा, ज्ञानचंद बंसल, डॉ. सुरुचि शर्मा, डॉ. शम्मी नागपाल आदि मौजूद रहे।

नभ-छोर स्थानीय-देश-विविध

क्या आज हम अपनी युवा पीढ़ी में 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का भाव पैदा कर सकते हैं : कुठियाला

हिसार/25 फरवरी/रिपोर्टर

दयानन्द महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर सात दिवसीय प्रदर्शनी आज से 03 मार्च तक महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यअतिथि के रूप में हरियाणा शिक्षा उच्चतर शिक्षा समिति के चेयरपर्सन प्रोफेसर भीके कुठियाला ने ऑनलाईन के माध्यम से तथा पूर्व मंत्री व आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली के उप प्रधान हरिसिंह सैनी ने किया। अतिथियों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र को पुष्प अर्पित करने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा बोस पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों का विवरण अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उन्होंने नेताजी की प्रतिभा, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान व समर्पण को रेखांकित करते हुए बताया कि उन्होंने देश सेवा के लिए किस तरह से आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था तथा उन्होंने किस तरह से विभिन्न देशों की यात्रा के उपरांत



जापान में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। समारोह के मुख्यअतिथि तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भीके कुठियाला ने कहा कि भारत के इतिहास की दो गाथाएं हमारे सामने हैं जिसमें एक गाथा लोकगीतों व कथाओं में मिलती है जो सम्पन्न एवं समृद्धशाली भारत की गौरवगाथा है तथा दूसरी गाथा यह है कि भारत एक बिखरा हुआ देश था। जिसे बाहर के लोगों ने आकर बनाया तथा बसाया था। आज स्कूलों तथा कॉलेजों में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है उसमें नेताजी की अनुपस्थिति क्यों है जबकि आज के युवा को यह समझने की जरूरत है कि नेताजी ने देश की आजादी के लिए अपने आदर्श एवं सुन्दर जीवन का त्याग क्यों किया ? क्या आज हम अपनी युवा पीढ़ी में "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का भाव पैदा कर सकते हैं ? आज हमें सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलकर हमारे देश की प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुख्यअतिथि हरिसिंह सैनी ने कहा कि हमें नेताजो के आदर्शों पर चलकर देश के पुनर्निमाण में अपना सहयोग देना है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने आयोजन के लिए इतिहास विभाग को बधाई दी तथा मुख्यअतिथि का परिचय समारोह में उपस्थित अतिथियों से करवाया। महाविद्यालय के विद्यार्थी श्रीकांत ने नेताजी के जीवन पर आधारित रागिनी सुनाकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। महाविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं डीएवी प्रबन्धक समिति के सदस्य देवेन्द्र उप्पल तथा प्रमोद लाम्बा के अतिरिक्त पंचनद शोध संस्थान के उपाध्यक्ष ज्ञानचन्द बंसल उपस्थित रहे। मंच का संचालन डॉ. सुरूचि शर्मा तथा डॉ. शम्मी नागपाल ने किया।



दो दिवसीय अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ सम्पन्न

Posted by: admin | in मनोरंजन | April 4, 2021 | 0 | 27 Views

Spread the love

दिल्ली: अवनीश राजवंशी प्रोडक्शन्स एवं डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अरावली इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल रविवार शाम अवॉर्ड सेरेमनी के साथ सम्पन्न हो गया । फ़ेस्टिवल के समापन एवं अवॉर्ड सेरेमनी में हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष प्रो बी. के. कुठियाला, उत्तराखंड हायर एजुकेशन अप ग्रेडेशन कमिटी की उपाध्यक्ष दीप्ति रावत, गुरुग्राम के कमिश्नर श्री विनय प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य मौजूद रहे ।

इस मौके पर प्रो. कुठियाला ने कहा कि अरावली इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल एक सफल आयोजन है जिसने यह सिद्ध किया है कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह की कितनी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता है । श्री अमित आर्य ने कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को फ़िल्मों के प्रति एक नई दृष्टि देते हैं । विनय प्रताप सिंह जी ने अरावली की कला संस्कृति एवं पर्यटन के लिए इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया ।

दीप्ति रावत ने कहा की फ़िल्मों के माध्यम से समाजिक चेतना और संवेदनशीलता को जागृत किया जा सकता है और इसके लिए अरावली फ़िल्म फ़ेस्टिवल जैसे आयोजन जरूरी है ।
समापन में दो दिन का ब्यौरा देते हुए फ़ेस्टिवल आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ राकेश योगी ने बताया कि इस फ़ेस्टिवल में 80 से देशों से 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को शामिल किया गया था । दो दिन में चुनी हुई 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। जिनमें से ऑस्कर विजेता फ़िल्म स्किन भी शामिल थी ।



इस आयोजन का एक ऑनलाइन संस्करण भी होगा, जो कि अमेरिका स्थित कंपनी FILMOCRACY के माध्यम से अप्रेल 3 से 10 तक स्ट्रीम होगा। अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के डायरेक्टर डॉ अवनीश राजवंशी जी ने जानकारी दी कि " हम पिछले कुछ वर्षों से यूरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में से एक, द हेग ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल ने IMDb कालीफाइंग स्टेटस अर्जित किया है । दिल्ली में इस फ़ेस्टिवल के आयोजन के साझीदार डायलॉग इनिशिएटिव फ़ाउंडेशन और अवेकन जॉय क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड है ।"

ADVERTISEMENT

Love a good laugh?
Show it!
Shop Now >
cafepress.com

FORMAR PRIME MINISTER LATE VAJPAYEE TEACHING A LESSON POLITICS TO THE PARLIAMENTA

Popular | Recent

एसपी सिटी अभिषेक व तबादले से जनता हैरान, काम, जनता के लिए सं
January 13, 2021

राफेल डील में दलाली व आया, फ्रांसीसी मीडिया एक मिलियन यूरो देने व
April 5, 2021

तीन तलाक पर सुप्रीम व आएगा बड़ा बदलाव
August 23, 2017

दिल्ली: बवाना में उपचु जारी, भाजपा-आप में व
August 23, 2017

449 निजी स्कूलों को टे सरकार, LG ने दी मंजूर
August 23, 2017

NEWS IN PICTURES



युवाओं की सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत : कुठियाला

जीजेयू में स्वावलंबी हिसार और आत्मनिर्भर भारत में विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर सेमिनार का किया आयोजन

जागरण संवाददाता हिसार : हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा है कि कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवाओं की सोच में परिवर्तन लाना होगा। युवा को समझाना होगा कि उसे नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। प्रो. कुठियाला गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित स्वावलंबी हिसार व आत्मनिर्भर भारत : विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।



गुजजेयू में सेमिनार को संबोधित करते मुख्यातिथि प्रो. बीके कुठियाला। • विज्ञप्ति

सेमिनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की। टास्क फोर्स कमेटी के फाउंडर सदस्य तथा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटेग्रेटिड एविएशन हब के सदस्य कैप्टन राजेश प्रताप सिंह विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. एनके बिश्नोई मुख्य वक्ता तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. अवनीश वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा थे। इस सेमीनार में विश्वविद्यालय के शिक्षक डा. पंकज खटक द्वारा कृत्रिम हाथ से सम्बंधित किए जा रहे नए उत्पाद के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यातिथि प्रो. कुठियाला ने कहा कि किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की भूमिका सर्वोपरि होती है। समाज शिक्षक पर सर्वाधिक विश्वास करता है। यही कारण है कि शिक्षक के पास बिना किसी चिंता के अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। शिक्षक शिक्षित ज्ञानवान व ज्ञान के प्रचार व प्रसार का वाहक होता है। शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थी का मानसिक रूप से इस प्रकार तैयार करें कि वो वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके।

उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा हर क्षेत्र में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। भारत के युवा के पास जितने मौके हैं, दुनिया के किसी अन्य युवा के पास इस प्रकार के मौके नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों के साथ तीन चरणों में सम्पर्क करना होगा। इन चरणों में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के सभी मुख्य बिन्दू समझाए जायेंगे।

भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बनाएं शोभा : प्रो. टंकेश्वर

कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि कोविड-19 के बाद हमें नई योजना की जरूरत है। भारतीय के रूप में हमें अपनी भूमिका ऐसे तैयार करनी है कि हम भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतियोगिता के योग्य तैयार करें। इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका निभानी होगी।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से ही देश चलता है। आने वाले समय में भारत में भी विश्वविद्यालयों की भूमिका बदलनी चाहिए। विशिष्ट वक्ता कैप्टन राजेश प्रताप सिंह ने हिसार हवाई अड्डे तथा यहां से सम्बंधित हवाई यात्राओं का पूर्ण विवरण दिया।

उन्होंने इंटेग्रेटिड एविएशन हब का ब्लू प्रिंट प्रस्तुत किया तथा बताया कि किस प्रकार और किन चरणों से गुजरकर हिसार को हवाई यात्रा का सपना पूरा हो सका है और भविष्य में यहां किस प्रकार की व्यवस्थाएं और सम्भावनाएं हैं।

सेमिनार

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने दी जानकारी

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी बनेंगे आत्मनिर्भर

भाई मिटो रिपोर्टर



सेमिनार में प्रो. बीके कुठियाला को सम्मानित करते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार।

हिसार। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवा की सोच में परिवर्तन लाना होगा।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों के साथ तीन चरणों में सम्पर्क करना होगा। इन चरणों में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का हल बताया जाएगा। प्रो. कुठियाला गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'स्वावलम्बी हिसार व आत्मनिर्भर भारत : विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर आयोजित सेमिनार के मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवा की सोच में परिवर्तन लाना होगा। युवा को समझाना होगा कि उसे नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। प्रो. कुठियाला गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित स्वावलंबी हिसार व आत्मनिर्भर भारत : विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। इस सेमीनार में विश्वविद्यालय के शिक्षक डा. पंकज खटक द्वारा कृत्रिम हाथ से सम्बंधित किए जा रहे नए उत्पाद के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यातिथि प्रो. कुठियाला ने कहा कि किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की भूमिका सर्वोपरि होती है। समाज शिक्षक पर सर्वाधिक विश्वास करता है। यही कारण है कि शिक्षक के पास बिना किसी चिंता के अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। शिक्षक शिक्षित ज्ञानवान व ज्ञान के प्रचार व प्रसार का वाहक होता है। शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वह विद्यार्थी का मानसिक रूप से इस प्रकार तैयार करें कि वो वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके।

उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा हर क्षेत्र में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। भारत के युवा के पास जितने मौके हैं, दुनिया के किसी अन्य युवा के पास इस प्रकार के मौके नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों के साथ तीन चरणों में सम्पर्क करना होगा। इन चरणों में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के सभी मुख्य बिन्दू समझाए जायेंगे।

हमारे उत्पादन विश्व के अन्य उत्पादों से बेहतर हों : मुख्य वक्ता प्रो. एनके बिश्नोई ने कहा कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि जो हम बनाए वह अच्छा हो, बल्कि यह है कि हमारा रक्षा, कौशल, सुरक्षा और अन्य दृष्टियों से विश्व के अन्य उत्पादों से बेहतर हो। अपनी भूमिका ऐसे तैयार करनी है कि हम भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतियोगिता के योग्य तैयार करें। इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका निभानी होगी। विशिष्ट वक्ता कैप्टन राजेश प्रताप सिंह ने इंटेग्रेटिड एविएशन हब की भविष्य की व्यवस्थाओं और संभावनाओं के बारे में बताया।

उन्होंने देशों और शहरों के उदाहरण देते हुए बताया कि एक छोटे से समाज के सुझाव, प्रयास को ले सकते हैं। विश्वविद्यालय इस मामले में मार्गदर्शक हो सकते हैं। कुलसचिव डॉ. अवनीश वर्मा ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बनें और स्वयं उद्योगों के मालिक बनें। कार्यक्रम संयोजक प्रो. संदीप राणा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में ही आत्मनिर्भर भारत का विजन हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की समस्या वहां के लोगों में पहलों को समझाने के बजाय समझने की आवश्यकता है।

प्रो. बी.के. कुठियाला ने कहा-युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है



हिसार | कल का भारत वैसा भारत होगा, जैसा आज हम इसे बनाना चाहते हैं। हमें आज के युवा की सोच में परिवर्तन लाना होगा। युवा को समझाना होगा कि उसे नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। कुछ ऐसे ही शब्दों से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने।

दरअसल, जीजेयू तथा हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाबधान में 'स्वावलम्बी हिसार व आत्मनिर्भर भारत, विश्वविद्यालय की भूमिका' विषय पर सेमीनार हुआ। सेमीनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने की। टास्क फोर्स कमेटी के फाउंडर सदस्य तथा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटेग्रेटिड एविएशन हब के सदस्य कैप्टन राजेश प्रताप सिंह विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. एनके बिश्नोई मुख्य वक्ता तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अवनीश वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा थे। मुख्य वक्ता प्रो. एन.के. बिश्नोई और कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संदीप राणा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. विकास वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। संचालन शिक्षिका डॉ. पल्लवी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के सह-समन्वयक डॉ. हरदेव सिंह उपस्थित रहे।



6 Haryana universities agree to try flexi-exam system

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, OCTOBER 19

HARYANA IS aiming to experiment with the "flexi-examination system" in its state universities, and at least six state universities have given their consent to the state's higher education council to try the new system. Under this system, a student may appear in any subject at any point of time and for that examination may be conducted by altering question setting up question paper from question bank etc.

The six universities that came forward for initially trying this system as a pilot project in select subjects/departments/courses and based on the learning to expand it further include Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani; Chaudhary Ranbir Singh University, Jind; Guru Jambheshwar Science and Technology University, Hisar; Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Sonipat; Shri Vishwakarma Skill University, Palwal and Ch. Devi Lal University of Science and Technology, Sirsa.

"Covid-19 pandemic has created a need to introduce innovations to the pattern of teaching and examination. The proposed flexi-examination system is a step in this direction. Disruptions may continue for an uncertain period and to create periods of methods have to be evolved by way of which students' interest may not suffer," a spokesman of Haryana State Higher Education Council said.

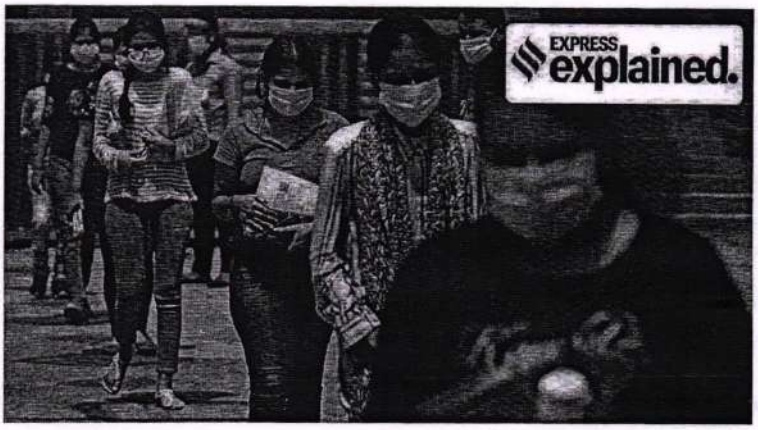
The council held consultation meetings with the Vice Chancellors of five state aided universities of Haryana.

"The governing body would adopt this concept in coming 4-5 years as there is a need to develop student centric system thereby giving an opportunity to the students to clear their backlogs. Of course, initially the universities should be left free to decide the courses/subjects to be

Explained: What is Haryana's 'flexi-examination' system for post-graduate students?

Education reforms in the time of Covid-19 envisage 're-appear' or 'compartment' students sitting again for their exam soon after the first attempt; they also open up a chance for brighter students to complete their four semesters in only three.

Written by **Varinder Bhatia**, Edited by Explained Desk | Chandigarh | Updated: October 20, 2020 7:40:22 am



Students at an exam centre in New Delhi. File/Express Photo by Praveen Khanna

The disruption in the education system in the country due to the Covid-19 pandemic has necessitated several education reforms to be put on fast track. One important dimension of the education system is examinations. Considering that the disruption in studies may continue for an uncertain period, Haryana State Higher Education Council has come out with a "flexi-examination system".

To begin with, at least seven out of the 17 government-aided universities of Haryana have agreed to introduce the system that will impact thousands of students of post-graduation courses. Gradually, the system will be adopted by all the 17 universities in post-graduation courses, followed by professional courses.

If the results are encouraging, then the flexi-examination system will also be introduced to the graduation courses. On average, 1.2 lakh-1.25 lakh students enroll in post-graduate courses in Haryana annually. What is the flexi-examination system, and how is it likely to impact students?

What exactly is the flexi-examination system announced by Haryana?

As the name suggests, the examination schedule shall be flexible for the students. There are two dimensions to this system.

23. Jan. 2021

आयोजन

आत्मनिर्भर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय: योजना एवं समाधान पर संगोष्ठी

आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न

पारस्परिक निर्भरता से ही हम हो सकते आत्मनिर्भर: प्रो. कुठियाला

हरिभूमि न्यूज» कुरुक्षेत्र

हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल धन अर्जित करना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ व्यापक परिवेश में है। पारस्परिक निर्भरता से ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारी अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना ही आत्मनिर्भरता है। हमें वर्तमान की अद्यतन परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिभाषित करना है। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है।



कुरुक्षेत्र। संगोष्ठी को संबोधित करते हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला। फोटो : हरिभूमि

यह विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने व्यक्त किये। वे मंगलवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूषा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 'आत्मनिर्भर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय: योजना एवं समाधान' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इससे पहले सरस्वती वंदना व दीप प्रज्ज्वलित कर विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ व्यक्ति या संस्थान को अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है। आपने निर्णय का संकल्प ही आत्मनिर्भरता है। हमारा उद्देश्य देश के युवाओं को मानवीय मूल्यों व जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्र का भाव लेकर उपयोगी नागरिक तैयार करना है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वदेशी तथा रोजगार के स्वभाव में भी बताया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक का कार्य पहला व पढ़ाने के साथ-साथ शोधन और सिखाना है। आज हमें समाज में अपनी भूमिका का समझने की जरूरत है। कोरोना ने हमें ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को बदला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परम्परा बहुत समृद्ध रही है। मंच का संचालन डॉ. कंसीलाल ने किया। डॉ. माहिर पूनिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

नैतिक मूल्यों से युक्त राष्ट्र का निर्माण ही उद्देश्य: प्रो. सोमनाथ

समाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। आत्मनिर्भरता केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ व्यापक परिवेश में है। पारस्परिक निर्भरता से ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारी अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना ही आत्मनिर्भरता है। हमें वर्तमान की अद्यतन परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिभाषित करना है। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है।



गोष्ठी का शुभारंभ करते हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला। संवाद

यह विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला ने व्यक्त किये। वे मंगलवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूषा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 'आत्मनिर्भर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय: योजना एवं समाधान' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इससे पहले सरस्वती वंदना व दीप प्रज्ज्वलित कर विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकता है, क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है वो ही अपने पैरों पर खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकता है, क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है वो ही अपने पैरों पर खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि आत्मनिर्भरता की बात तब चली जब भारत के सर्वोच्च नेतृत्व ने आत्मनिर्भरता की बात कुछ माह पहले की थी। इसमें कहीं से भी कोरोना के समय में हमें यह समझ आया कि एक देश पर निर्भरता ठीक नहीं है। उस समय पूरे विश्व जिसमें अमेरिका, जर्मनी देशों ने भी आत्मनिर्भरता की बात की। एक गरीब मुक्त समाज, समृद्ध समाज का निर्माण व नैतिक मूल्यों से युक्त राष्ट्र का निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता का अर्थ नैतिक मूल्यों के साथ युक्त रोजगार युक्त होना है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने की चुनौती है। 2022 में नैक का मूल्यांकन होना है। हम जब युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें तभी गरीबी मुक्त समाज का निर्माण होगा। हमें केवल विद्यार्थियों को डिग्री नहीं देनी बल्कि उन्हें नैतिक मूल्य भी देना होगा। ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना हो। संयोजक डॉ. प्रदीप चौहान ने कहा कि कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर अभियान आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत का पहला कदम है। डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. मंजुला चौधरी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, नई शिक्षा नीति 2020, एनआईआरएफ रैंकिंग, स्वयं के तहत चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम, आगामी प्लान, हैड हॉल्डिंग, फास्ट्रक्चर इनोवेशन, शोध के क्षेत्र में संभावनाएं, नैक 2022 के लिए तैयार होने, ऑनलाइन व चॉयसेड लर्निंग, डिजीटल लर्निंग के बारे में चर्चा की। कुलसचिव डॉ. संजीव शर्मा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अनिल बलिराड, डॉ. बंसीलाल, डॉ. महाबीर पूनिया, प्रो. बजीर नेहरा, प्रो. आरएमपी जायसवाल और डॉ. कृष्ण पाडे मौजूद रहे।

काबिलियत को बढ़ाना ही आत्मनिर्भरता: प्रो. बीके

- सीनेट हॉल में युवा व सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग और पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र की ओर से आत्मनिर्भरता पर गोष्ठी

भास्कर न्यूज | कुरुक्षेत्र

केयू के सीनेट हॉल में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग और पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र की ओर से आत्मनिर्भरता पर गोष्ठी की गई। इसमें मुख्यातिथि हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला रहे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल धन अर्जित करना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ व्यापक परिवेश में है। पारस्परिक निर्भरता से ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारी अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना ही आत्मनिर्भरता है। हमें वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिभाषित करना है। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है। प्रो. कुठियाला ने कहा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बना सकता है, क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है वो ही अपने पैरों पर खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि आत्मनिर्भरता की बात तब चली जब भारत के सर्वोच्च नेतृत्व ने आत्मनिर्भरता की बात कुछ माह पहले की थी। इसमें कहीं से भी कोरोना के समय में हमें यह समझ आया कि एक देश पर निर्भरता ठीक नहीं है। उस समय पूरे विश्व जिसमें अमेरिका, जर्मनी देशों ने भी आत्मनिर्भरता की बात की। एक गरीब मुक्त समाज, समृद्ध समाज का निर्माण व नैतिक मूल्यों से युक्त राष्ट्र का निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता का अर्थ नैतिक मूल्यों के साथ युक्त रोजगार युक्त होना है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखने की चुनौती है। 2022 में नैक का मूल्यांकन होना है। हम जब युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें तभी गरीबी मुक्त समाज का निर्माण होगा। हमें केवल विद्यार्थियों को डिग्री नहीं देनी बल्कि उन्हें नैतिक मूल्य भी देना होगा। ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना हो। संयोजक डॉ. प्रदीप चौहान ने कहा कि कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर अभियान आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत का पहला कदम है। डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. मंजुला चौधरी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति, नई शिक्षा नीति 2020, एनआईआरएफ रैंकिंग, स्वयं के तहत चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम, आगामी प्लान, हैड होल्डिंग, फास्ट्रक्चर इनोवेशन, शोध के क्षेत्र में संभावनाएं, नैक 2022 के लिए तैयार होने, ऑनलाइन व चॉयसेड लर्निंग, डिजीटल लर्निंग के बारे में चर्चा की। कुलसचिव डॉ. संजीव शर्मा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अनिल बलिराड, डॉ. बंसीलाल, डॉ. महाबीर पूनिया, प्रो. बजीर नेहरा, प्रो. आरएमपी जायसवाल और डॉ. कृष्ण पाडे मौजूद रहे।



कुरुक्षेत्र। केयू सीनेट हॉल में गोष्ठी को संबोधित करते उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला।

पारस्परिक निर्भरता से ही हम आत्मनिर्भर हो सकते : प्रो. कुठियाला



संगोष्ठी को संबोधित करते हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बीके कुठियाला।

कुरु क्षेत्र (जसवीर दुग्गल) : हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो.. बीके कुठियाला ने कहा कि आत्मनिरभरता केवल धन अर्जित करना नही बल्कि आत्मनिरभरता का अर्थ व्यापक परिवेश से है। पारस्परिक निर्भरता से ही हम आत्मनिरभर हो सकते हैं। हमारी अपनी कार्बिलियत को बढ़ाना ही आत्मनिरभरता है। हमे वर्तमान की अद्यतन परिस्थितियो के अनुसार खुद को परिभाषित करना है। आत्मनिरभर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिरभरता मे है। वे मगलवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एव सास्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा पचनद शोध सस्थान अध्ययन केन्द्र, कुरुक्षेत्र के सयुक्त तत्वाधान मे आत्मनिरभर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय: योजना एव समाधान' विषय पर आयोजित सगोष्ठी मे बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इससे पहले सरस्वती वदना व दीप प्रज्ज्वलित कर विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सजीव शर्मा, प्रो. वजीर नेहरा, प्रो. आरएमपी जायसवाल, डॉ. कृष्ण पाण्डे सहित डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष व पचनद शोध अध्ययन केन्द्र के सदस्य मौजूद रहे।

ऑनलाइन स्थानांतरण नीति व अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने दिए सुझाव

उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बीके कुठियाला की अध्यक्षता में बैठक

भास्कर न्यूज | रोहतक

हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन स्थानांतरण नीति व अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक की। अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष डा. सुखबीर सिंह ने बताया कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्तों की वजह से प्रोफेसर साथियों के सीनियर स्केल, सलेक्शन ग्रेड और एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रेड अटके हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2013 में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था तथा जुलाई 2014 में इसे लागू करने के लिए महाविद्यालयों का वर्गीकरण जारी किया गया। परंतु उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नीति को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया जो उचित कदम नहीं था। उन्होंने सुझाव रखा कि जुलाई 2014 तक जिन साथियों के ग्रेड लंबित हैं, उनको बिना ग्रामीण सेवा के ग्रेड जारी किए जाए। बहुत से विषयों में ग्रामीण सेवा की शर्तें को पूरा करना अत्यंत मुश्किल है और ऐसे विषयों में ग्रामीण सेवा की शर्तों को समाप्त किया जाए या कम किया जाए।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नई नियुक्तियां देते समय प्राथमिकताओं को उनकी मर्जी के विरुद्धाभाव शहरी महाविद्यालयों में नियुक्ति दे दी जाती है जिसके कारण चाहते हुए भी वे लंबे समय तक ग्रामीण सेवा की शर्तें को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते। सिर्फ जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालय को ही अर्बन कॉलेज माना जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसरों को एक स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात ग्रामीण कॉलेज को चयन करने की बाध्यता से छूट दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों को ग्रामीण सेवा करने का मौका मिल सके। एसोसिएशन की ओर से स्थानांतरण नीति और अनिवार्य ग्रामीण सेवा को प्राध्यापकों के हित में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की मांग रखी गई।

इस बैठक में हरियाणा गवर्नमेंट कालेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। बैठक के समापन पर हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला ने कहा कि प्राप्त सुझावों के आधार पर अनिवार्य ग्रामीण सेवा और ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर सरकार को हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की ओर से अपनी सिफारिश भेजी जाएगी जिससे छात्रों व शिक्षकों के हितों को वरीयता दी जाएगी।

हरियाणा वाटिका

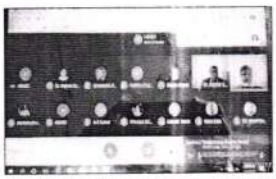
हरियाणा

भिवानी, बुध

ऑनलाइन स्थानांतरण नीति और अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने रखे सुझाव

अनिल वाल्मिया

वाटिका@भिवानी। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन स्थानांतरण नीति व अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक की। अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष डा. सुखबीर सिंह ने बताया कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्तों की वजह से प्रोफेसर साथियों के सीनियर स्केल, सलेक्शन ग्रेड और एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रेड अटके हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2013 में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था तथा जुलाई 2014 में इसे लागू करने के लिए महाविद्यालयों का वर्गीकरण जारी किया गया। परंतु उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नीति को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया जो उचित कदम नहीं था। उन्होंने सुझाव रखा कि जुलाई 2014 तक जिन साथियों के ग्रेड लंबित हैं, उनको बिना ग्रामीण सेवा के ग्रेड जारी किए जाए। बहुत से विषयों में ग्रामीण सेवा की शर्तें को पूरा करना अत्यंत मुश्किल है और ऐसे विषयों में ग्रामीण सेवा की शर्तों को समाप्त किया जाए या कम किया जाए।



बैठक का आयोजन हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा और ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर शिक्षक संगठनों के सुझावों के लिए किया गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नई नियुक्तियां देते समय प्राथमिकताओं को उनकी मर्जी के विरुद्धाभाव शहरी महाविद्यालयों में नियुक्ति दे दी जाती है जिसके कारण चाहते हुए भी वे लंबे समय तक ग्रामीण सेवा की शर्तें को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते। सिर्फ जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालय को ही अर्बन कॉलेज माना जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसरों को एक स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात ग्रामीण कॉलेज को चयन करने की बाध्यता से छूट दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों को ग्रामीण सेवा करने का मौका मिल सके। एसोसिएशन की ओर से स्थानांतरण नीति और अनिवार्य ग्रामीण सेवा को प्राध्यापकों के हित में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की मांग रखी गई।

12 Jan. 2024

'अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्तों के कारण प्रोफैसरों के सीनियर स्केल, सिलैक्शन ग्रेड और एसोसिएट प्रोफैसर के ग्रेड अटके हैं : डा. सुखबीर'

भिवानी, 12 जनवरी(ब्यूरो): अम्बेदकर प्रोफैसर्स एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव डा. राजेश लांग्यान ने बताया कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के निमंत्रण पर अम्बेदकर प्रोफैसर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधि आज उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफैसर बृजकिशोर कुठियाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित हुए।

हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से यह बैठक अनिवार्य ग्रामीण सेवा और ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर शिक्षक संगठनों की तरफ से सुझाव रखने के लिए आयोजित की गई थी।

बैठक में अम्बेदकर प्रोफैसर्स एसोसिएशन के प्रधान डा. सुखबीर सिंह ने कहा कि अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्तों की वजह से प्रोफैसर साथियों के सीनियर स्केल, सिलैक्शन ग्रेड और एसोसिएट प्रोफैसर के ग्रेड अटके हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर-2013 में इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी किया गया था और जुलाई 2014 में इसे लागू करने के लिए महाविद्यालयों का वर्गीकरण जारी किया गया परंतु उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नीति को रैट्रास्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया, जो उचित कदम नहीं था। उन्होंने सुझाव रखा कि जुलाई 2014 तक जिन साथियों के ग्रेड लम्बित हैं उनको बिना ग्रामीण सेवा के ग्रेड जारी किए जाएं।

डा. राजेश लांग्यान ने कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में 300 पद स्वीकृति वाले विषयों की बाध्यता को हटा सभी विषयों को शामिल किया जाए। सहायक प्रोफैसर या एसोसिएट प्रोफैसर जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनको ग्रामीण सेवा से छूट दी जानी चाहिए। जिन सहायक प्रोफैसर या एसोसिएट प्रोफैसर की ग्रामीण सेवा पूरी हो चुकी है उसे ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में 10 महाविद्यालयों में पहला ऑप्शन शहरी दिया जाए। उन्होंने कहा कि नियमित प्राध्यापकों के स्थानांतरण के समय एक्सटैंशन लैक्चरर के स्थान को रिक्त माना जाए।

इस अवसर पर संगठन प्रधान डा. सुखवीर सिंह, उपप्रधान प्रोफैसर सूबेसिंह, कार्यकारिणी सदस्य डा. महेंद्र सिंह बागी, डा. रेणु बाला और संगठन की सक्रिय सदस्य डा. रेणु बाला आदि ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए।

1.4.2021 हरियाणा

'नई शिक्षा नीति भारत और भारतीयों के अनुरूप : बी.के. कुठियाला'

भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की महामारी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारत की शिक्षा नीति को बदलने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और भारत की सुप्रीम कोर्ट के लॉ मैंबर और लॉ कमीशन रहे मैकाले की शिक्षा नीति देश में 70 सालों से चली आ रही थी। विद्यार्थी नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने में सक्षम बन पाएगा। पंजाब केसरी ने इस बारे में हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बी.के. कुठियाला से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें इस नई शिक्षा नीति के बारे में सांझा कीं, जिसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं :-



प्रश्न : नई शिक्षा प्रणाली क्या है और इसे लागू करने के प्रयास कहां तक सार्थक हुए और कब तक टारगेट पूरा कर पाएंगे?

उत्तर : नई शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 कहा जा रहा है जोकि शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने की योजना है, जिसमें कुछ परिवर्तन केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने करने हैं, कुछ विश्वविद्यालयों ने, कुछ महाविद्यालयों ने और कुछ विद्यालयों ने करने हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने इस सारी शिक्षा नीति का विश्लेषण कर एक रैडी रेकनर बनाया है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के लिए जो केंद्र सरकार ने टारगेट रखा है उससे पहले ही हम उसे अचीव कर लेंगे।

प्रश्न : नई शिक्षा नीति में क्या बच्चों के रोजगार को लेकर भी कुछ नया रहेगा ?

उत्तर : इस शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा केवल मातृभाषा में रहेगी। बच्चा अपनी मां के साथ अपने घर में जो भाषा बोलता है, छठी कक्षा तक वही भाषा उपयोग में होगी। जैसे पंजाब का बच्चा घर में पंजाबी बोलता है तो गुरुमुखी में ही शिक्षा ग्रहण करने की उसके लिए सुविधा और उसका अधिकार भी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं को भी वह सीख सकता है। उच्च शिक्षा में ऐसा प्रावधान होगा कि वह अपनी मातृभाषा में या हिंदी में शिक्षा प्राप्त कर सके। हम अपनी मातृभाषा में अधिक सीखेंगे, अधिक समझेंगे और उसका अधिक प्रयोग कर पाएंगे। क्लास छठी से उसे इस बात की जानकारी दी जाएगी कि समाज में क्या-क्या काम कर वह जीवनयापन कर सकता है। छठी कक्षा में एक बैग लैस डे का प्रावधान है। उस दिन बच्चे स्कूल में किताबें नहीं लाएंगे। स्कूल के अध्यापक बच्चों को समाज में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि समाज में क्या-क्या काम किए जा रहे हैं।

प्रश्न : अध्यापकों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग क्या है और उसे कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है ?

उत्तर : पिछले लगभग 15 साल से यह आवश्यकता महसूस हो रही थी कि यह जो डब्ल्यू.डब्ल्यू. इंटरनेट और मोबाइल की टैक्नोलॉजी का प्रयोग हम शिक्षा को और विस्तार देने और सुगम बनाने में करें। यह चल ही रहा था कि कोविड के कारण लॉकडाऊन हो गया। तो हमारे पास यह उपाय था कि हम ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों से बात करें, उन्हें पढ़ाएं और सिखाएं। यह सिद्ध हो गया कि आने वाले समय में नार्मल स्थिति में भी यह प्रक्रिया चलने वाली है। इसलिए अभी तक जो हमारा प्राध्यापक में क्लास रूम में सिखाने के लिए योग्यता और क्षमता थी। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 30 घंटे का एक कोर्स तैयार बनाया है, जिसे ऑनलाइन ही कोई भी अध्यापक कर सकता है। इसमें डिजिटल पढ़ाने की उसमें क्षमता हो जाएगी।

प्रश्न : बहुत से गांवों में इंटरनैट की उपलब्धता नहीं है?

उत्तर : यह बात भी हमारे ध्यान में है। धीरे-धीरे ऐसे डार्क एरिया को आइडैंटिफाई किया जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर्स से बात कर कहा जा रहा है कि सब जगह डाटा 3जी और 4जी में उपलब्ध हो। इस कमजोरी को भी पूरा कर रहे हैं। कुछ केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे जिनमें यह डाटा होगा और विद्यार्थियों को सुविधा दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों को फिर भी यह उपलब्ध नहीं होता है। वह कॉलेज/यूनिवर्सिटी में आकर इस डाटा का प्रयोग कर सकेंगे।

प्रस्तुति : चंद्रशेखर पटो

कार्यक्रम | चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित

विद्यार्थी रुचि के अनुसार करें करियर का चयन : प्रो. कुठियाला

जागरण संवाददाता, सिरसा : हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रो. बीके कुठियाला ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर का चयन करना चाहिए। भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है और अपनी युवा शक्ति की बदौलत भविष्य में भारत की उपयोगिता, प्रभाव तथा महत्व विश्व में सबसे अधिक होगा। कुठियाला शुक्रवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा आयोजित ईंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्य अतिथि प्रो. कुठियाला तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक द्वारा इ-लाइब्रेरी के लिंक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. राकेश वधवा भी उपस्थित थे।



सिरसा। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बीके कुठियाला का स्वागत करते कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक, कुलसचिव राकेश वधवा व अन्य। • विज्ञप्ति

नई शिक्षा नीति को लागू करने में विश्वविद्यालय अग्रणी

प्रो. कुठियाला ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अत्यंत भाग्यशाली है जो स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे है। हरियाणा के युवाओं में उत्साह, जोश और रिस्क लेने का जज्बा अन्य प्रदेशों के युवाओं की तुलना में अत्यधिक है और इसी वजह से यहां के युवा नये नये उद्यम स्थापित करके देश भर में कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार क्रियान्वित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में चलाये जा रहे हैं और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय इस नीति को क्रियान्वित करने में अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अग्रणी है। इन नवीन प्रोग्राम्स में रोजगार की अपार संभावनाएं है। प्रोफेसर कुठियाला ने कहा कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। यदि विद्यार्थी दिन में 100 शब्द सुनता है तो उसे केवल एक शब्द ही बोलना चाहिए और सुने तथा पढ़े हुए शब्दों पर मनन अधिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शैक्षणिक तथा औद्योगिकी जगत में अवसरों के भंडार लेकर आई है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हित में हर सम्भव सुविधाओं जैसे हॉस्टल, छात्रवृति, वाईफाई, पुस्तकालय आदि प्रदान की जाएगी इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा पढ़ने तथा लिखने की सिख दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के अधीन 62 महाविद्यालय है तथा वर्तमान में 52000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.के. कुठियाला तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक द्वारा इ-लाइब्रेरी के लिंक का विमोचन भी किया गया जिससे विद्यार्थी किसी भी समय कही पर भी सरलता से एक्सेस कर सकते है तथा छः लाख से अधिक इ-रेसोर्सिं? का लाभ उठा सकते है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राकेश वधवा भी उपस्थित थे।

विद्यार्थियों को दी जानकारी

इससे पूर्व शैक्षणिक मामलों के अधिष्ठाता प्रो. सुरेश कुमार महलावत ने विश्वविद्यालय की ओवरआल डेवलपमेंट तथा एचीवमेंट के बारे में विद्यार्थियों को बताया तथा यूनिवर्सिटी स्कूल फार ग्रेजुएट स्टडीज के अधिष्ठाता प्रो. सुशील ने मल्टी-डिस्प्लीनरी प्रोग्राम के बारे में विद्यार्थियों को बारीकी से बताया। इसके उपरांत विधि विभाग के अध्यक्ष प्रो. अशोक मलकड़ तथा यूनिवर्सिटी कालेज के प्राचार्य डा. सुल्तान ढांडा ने विश्वविद्यालय में बारहवीं के उपरांत चल रहे कोर्सेज के बारे में तथा भावी संभावनाओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की।

प्रादेशिक

युवा शक्ति की बदौलत विश्व में बढ़ेगा भारत का प्रभाव: कुठियाला



पल पल न्यूज: सिरसा, 10 सितम्बर। भारतीय दर्शन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है और विद्यार्थियों को अपनी रूचि के अनुसार कैरियर का चयन करना चाहिए। भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं का देश है और अपनी युवा शक्ति की बदौलत भविष्य में भारत की उपयोगिता, प्रभाव तथा महत्व विश्व में सबसे अधिक होगा। ये विचार हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रोफेसर बी.के. कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा आयोजित स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए व्यक्त किये। प्रोफेसर कुठियाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के नवआगंतुक विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि वे अत्यंत भाग्यशाली है जो स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं में उत्साह, जोश और रिस्क लेने का जज्बा अन्य प्रदेशों के युवाओं की तुलना में अत्यधिक है और इसी वजह से यहाँ के युवा नये नये उद्यम स्थापित करके देश भर में कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार क्रियान्वित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में चलाये जा रहे हैं और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय इस नीति को क्रियान्वित करने में अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अग्रणी है। इन नवीन प्रोग्राम्स में रोजगार की अपार संभावनाएं है। प्रोफेसर कुठियाला ने कहा कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक श्रवण और अध्ययन करना चाहिए। यदि विद्यार्थी दिन में 100 शब्द सुनता है तो उसे केवल एक शब्द ही बोलना चाहिए और सुने तथा पढ़े हुए शब्दों पर मनन अधिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शैक्षणिक तथा औद्योगिकी जगत में अवसरों के भंडार लेकर आई है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हित में हर सम्भव सुविधाओं जैसे हॉस्टल, छात्रवृति, वाईफाई, पुस्तकालय आदि प्रदान की जाएगी इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन वचनबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा पढ़ने तथा लिखने की सिख दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के अधीन 62 महाविद्यालय है तथा वर्तमान में 52000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.के. कुठियाला तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक द्वारा इ-लाइब्रेरी के लिंक का विमोचन भी किया गया जिससे विद्यार्थी किसी भी समय कही पर भी सरलता से एक्सेस कर सकते है तथा छः लाख से अधिक इ-रेसोर्सिं? का लाभ उठा सकते है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राकेश वधवा भी उपस्थित थे।

हरियाणा के युवा उद्यमी बनने का रिस्क उठाने में आगे

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम में बोले कुठियाला

संवाद न्यूज एजेंसी



कार्यक्रम के दौरान भंगड़े की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। संवाद

सिरसा। चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम किया गया। जिसमें हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रो. बीके कुठियाला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। प्रो. कुठियाल ने कहा कि हरियाणा के युवाओं की बड़ी सोच के कारण उद्यमी बनने का रिस्क उठाने में आगे है।

प्रो. कुठियाला ने नवआगंतुक विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि वे अत्यंत भाग्यशाली है जो स्कूल से सीधे विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे है। हरियाणा के युवाओं में उत्साह, जोश और रिस्क लेने का जज्बा व अन्य प्रदेशों के युवाओं की तुलना में अत्यधिक है और इसी वजह से यहां के युवा नए- नए उद्यम स्थापित करके देशभर में कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार क्रियान्वित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में चलाए जा रहे है और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय इस नीति को क्रियान्वित करने में अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अग्रणी है। इन नवीन प्रोग्राम्स में रोजगार की अपार संभावनाएं है। प्रो. कुठियाला ने कहा कि यदि विद्यार्थी दिन में 100 शब्द सुनता है तो उसे केवल एक शब्द ही बोलना चाहिए और सुने, पढ़े शब्दों पर मनन अधिक करना चाहिए। विश्वविद्यालय की कॅरियर काउंसलिंग सेल विद्यार्थियों में लाइफ काउंसिलिंग का कौशल विकसित करने पर जोर दे ताकि विद्यार्थियों को अच्छा सुनकर, अच्छा देखकर, अच्छा बोलकर एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। विश्वविद्यालय के अधीन 62 महाविद्यालय है तथा वर्तमान में 52000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे है। अंत में युवा कल्याण निदेशालय द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मंच का संचालन युवा कल्याण निदेशिका डॉ. मंजू नेहरा ने किया। इसके उपरांत प्रो. कुठियाला ने विश्वविद्यालय के विवेकानंद पुस्तकालय का अवलोकन किया और पुस्तकालय को बेहतर बनाने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी वार्ने और उनके स्टाफ को भी सुझाव दिए।

सौगात

विद्यार्थियों के लिए एंड्रॉयड व एपल फोन के लिए अलग-अलग लिंक बनाया गया

ई-लाइब्रेरी में 6 लाख से अधिक माध्यमों से पढ़ सकेंगे विद्यार्थी

अनुपमा जाखड़

सिरसा। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अपने विषय से संबंधित पुस्तकें ढूंढने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने नई पहल करते हुए विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी लांच की है। जिसमें 6 लाख से अधिक ऐसे स्त्रोत डाले गए है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कहीं पर भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं।



प्रो. बीके कुठियाल को सम्मानित करते कुलपति प्रो. अजमेर सिंह। संवाद

हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन प्रो. बीके कुठियाला व कुलपति प्रो. अजमेर सिंह ने शुक्रवार को ई लाइब्रेरी के एक्सेस को लांच किया। इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी कहीं भी बैठकर अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को पढ़ सकता है। ई लाइब्रेरी में रिसर्च थीसिज, लेक्चर वीडियो, ई बुक, ऑडियो-वीडियो लेक्चर व अन्य ऐसे स्त्रोत दिए गए है। जिसका प्रयोग करके विद्यार्थी पढ़ सकते है। ई लाइब्रेरी का एक्सेस जल्द ही विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा। जिसे विद्यार्थी अपने लैपटॉप में लिंक एक्सेस कर खोल सकते हैं। वहीं जिन विद्यार्थियों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए एंड्रॉयड व एपल फोन के लिए अलग-अलग लिंक बनाया गया है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी ई लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते है। वहीं ई लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों के समय की भी बचत होगी। विश्वविद्यालय में स्थापित विवेकानंद लाइब्रेरी है जिसका बंद होने का समय शाम 5 बजे है। ई लाइब्रेरी के बाद अब विद्यार्थियों को समय को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। किसी भी समय विद्यार्थी ई लाइब्रेरी के माध्यम से किसी भी समय पढ़ पाएंगे। (संवाद)

ई लाइब्रेरी में पाठ्य सामग्री

- 6 लाख पढ़ने के स्त्रोत
- 10 हजार ई पुस्तकें
- 9 हजार विशेषज्ञों से बातचीत
- 16 हजार ऑडियो पुस्तकें
- 4 भाषाओं का विकल्प
- 50 हजार न्यूज पेपर

"चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ई-लाइब्रेरी लांच की गई है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी किसी भी समय पुस्तकों को पढ़ सकते है। वहीं ई-लाईब्रेरी में पुस्तकों के साथ-साथ एक्सपर्ट द्वारा वीडियो भी अपलोड की गई है जिसे विद्यार्थी कभी भी देखकर पढ़ सकते है।
- प्रो. अजमेर सिंह मलिक, कुलपति चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय

विद्यार्थी निशुल्क पढ़ सकेंगे पुस्तकें

ई लाइब्रेरी में जो विद्यार्थी पुस्तकें खरीदने में समर्थ नहीं है वो इन्हें निशुल्क में पुस्तकें पढ़ सकेंगे। वहीं विद्यार्थियों को अपनी मनपसंद महंगी किताबों को खरीदना नहीं पड़ेगा। जिससे विद्यार्थियों के पैसों की बचत होगी। वहीं ई लाइब्रेरी में दुनिया भर के शीर्ष विद्यालयों के अध्यापकों को पढ़ने, सुनने व देखने का मौका मिलेगा।

'संवाद भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता'

फरीदाबाद, 22 अक्तूबर (पूजा शर्मा): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी मानी जाती है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न सिर्फ अधिकार है बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता भी रही है। ये विचार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने बतौर मुख्य अतिथि जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा भारतीय दृष्टि' राष्ट्रीय संगोष्ठी में रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने की।



हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. बृज किशोर कुठियाला की पुस्तक 'संवाद का स्वराज' का लोकार्पण करते हुए कुलपति प्रो. दिनेश कुमार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण।

इस उपलक्ष में प्रो. कुठियाला द्वारा लिखित पुस्तक 'संवाद का स्वराज' का लोकार्पण भी किया गया। प्रभात प्रकाशक द्वारा प्रकाशित इस 184 पन्नों की पुस्तक में कुल 27 अध्याय है। प्रो. कुठियाला ने कहा कि अभिव्यक्ति केवल अधिकार नहीं, अपितु समग्र मानव संवाद है जो एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पहले, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रबुद्ध भारतीय चिंतक एवं वरिष्ठ समाजसेवी नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के पूरकता के संबंध को स्वीकार करते हुए बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सके, समाज समावेशी बने एवं विश्व में भारतीय संविधान जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा हेतु प्रसिद्ध है, की गरिमा बरकरार रहे।

विशिष्ट वक्ता भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के महानिदेशक प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ एक स्वतंत्र संस्कृति से ही संभव हो पाई है।भारतीय संस्कृति और दर्शन प्राकृतिक रूप से सहभागी है।



विद्यार्थियों को संबोधित करते प्रोफेसर बीके कुठियाला। विज्ञप्ति

भारत युवाओं का देश, इसलिए संभावनाएं भी ज्यादा : प्रो. कुठियाला

संवाद न्यूज एजेंसी

जींद। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा देश है। जब भी कोई देश सबसे युवा वाला देश बनाता दुनिया में वह एक नंबर पर होता है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चीन के बाद अब भारत का समय है।

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय प्रदेश स्तरीय शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व में अग्रणी होगा। युवा करियर चयन नहीं करके जीवन का चयन करें। उन्होंने कहा कि 21 प्रतिशत आईएएस, 33 प्रतिशत डॉक्टर 10 प्रतिशत अध्यापक पांच साल नौकरी करने के बाद कहते हैं अपना कॅरियर गलत चयन कर लिया। इसलिए जीवन का चयन करना चाहिए।

इस दौरान एनएसएस के प्रभारी डॉ. भगत सिंह राष्ट्रीय सेवा योजना के के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने भी शिकरत की।

करते हुए। ● जागरण

कार्यक्रम सीआरएसयू में प्रथम राष्ट्र विषय पर सात दिवसीय प्रांतीय शिविर का आयोजन

आध्यात्मिक रूप से विश्व में प्रथम होगा भारत

जागरण संवाददाता, जींद : चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा प्रथम राष्ट्र विषय पर सात दिवसीय प्रांतीय शिविर का आयोजन किया।

मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला रहे और उनका स्वागत प्रांतीय अधिकारी डा. भगत सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक डा. जितेंद्र कुमार ने सात दिवसीय प्रांतीय शिविर कार्यक्रम का विस्तारपूर्वक रखे। कार्यक्रम के अध्यक्षता कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। जैसे सरकारी नौकरी दो फीसदी और कार्पोरेट पांच फीसदी है व निजी 10 प्रतिशत है। वहीं स्वरोजगार से 75 प्रतिशत रोजगार मिलता है। इसलिए आत्मनिर्भर कि तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है।



चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रोफेसर बीके कुठियाला। ● जागरण

सभी राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र ही प्रथम है : कुठियाला

मुख्य अतिथि प्रोफेसर कुठियाला ने कहा कि भारत सबसे ज्यादा युवा वाला देश बन गया है। जब भी कोई देश सबसे युवा वाला देश बनाता दुनिया में वह एक नंबर पर होता है। जैसे उदाहरण अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चीन अब भारत का समय है। भारत आर्थिक रूप से प्रथम न होकर सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से भारत दुनिया में प्रथम होगा। विद्यार्थी को प्रेरित करते हुए कहा कि करियर चयन न करके जीवन का चयन करें। एक सर्वे 21 प्रतिशत आइएएस, 33 प्रतिशत डाक्टर, दस प्रतिशत अध्यापक पांच साल नौकरी करने के बाद कहते है अपना करियर गलत चयन कर लिया। राष्ट्र के बारे में सोचे इसलिए राष्ट्र प्रथम है। कुलसचिव डा. राजेश बंसल ने सभी वक्ताओं का आभार जताया।

अनुलग्नक

PART I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2018

No. Leg.7/2018.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 27th March, 2018 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 4 OF 2018

THE HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL ACT, 2018

AN

ACT

to promote academic excellence and social justice by obtaining academic input for policy formulation and perspective planning, ensuring autonomy and greater accountability of all institutions of Higher Education in the State and guiding the growth of Higher Education in accordance with the socio-economic requirements of the State as per the requirement of Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyaan and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana State Higher Education Council Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 28th February, 2018.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Chairperson” means the Chairperson of the Council;

(b) “College” means a college or institution including autonomous college maintained or approved or affiliated to any University which provides facility of studying in syllabi from admission till examination;

(c) “Commission” means the Haryana State Higher Education Commission constituted under section 12;

(d) “Council” means the Haryana State Higher Education Council constituted under section 3;

(e) “Higher Education” means any education stream whether financial, technical including research studies that leads to award of degree, diploma or certificate but does not include Medical, Agriculture, Animal Husbandry and Horticulture stream;

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

(f) “Institution” means an academic institution of Higher Education *including Govt., Govt. Aided, Private Colleges and Universities* maintained by, or admitted to the privileges of the University;

(g) “Member” means a member of the Council and includes the Chairperson and Vice-Chairperson;

(h) “Prescribed” means prescribed by the rules framed under this Act; (i) “State” means the State of Haryana;

(j) “State Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(k) “University” means any University established by an Act passed by the State Legislature;

(l) “University Grants Commission” means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);

(m) “Vice-Chairperson” means Vice-Chairperson of the Council.

Constitution of Council.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute the Haryana State Higher Education Council consisting of the following members, namely:-

(a) an educationist with proven leadership qualities or a famous intellectual – Chairperson;

(b) an education administrator of all India repute who is or has worked at least on the post of Professor or equivalent post – Vice-Chairperson;

(c) *State Project Director*- Member Secretary;

(d) ~~State Project Director – Member;~~

(e) *Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Higher Education Department, Haryana or his representative not below the rank of Director, Higher Education Department, Haryana-Member* ~~a representative of Higher Education Department not below the rank of Deputy Director~~ – Member;

(f) *Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Technical Education Department, Haryana or his representative not below the rank of Director, Technical Education Department, Haryana-Member* ~~a representative of Technical Education Department not below the rank of Deputy Director~~- Member;

(g) a representative of Finance Department not below the rank of Joint Secretary – Member;

(h) fifteen members from the field of art, science, technology, culture, social sector and industry and professional Education etc.- Member: Provided that ten members of the Council shall be from the State and five members shall be from other States and shall be of national repute. *Provided further that the State Government on the recommendation of Chairperson of the Council may add additional members/special invitees, as may be required.*

(i) Vice-Chancellors of any three Universities of the State – Member;

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

(j) two Principals of autonomous or affiliated colleges – Member;

(k) one member nominated by the Ministry of Human Resource Development, Government of India – Member.

(2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(3) The tenure of each nominated member shall be for a period of six years and one-third of the members shall retire after every two years. The Council shall nominate seven new members in every two years.

(4) ~~The meeting of the Council shall be held once every three months.~~

(5) ~~The quorum of the meeting of the Council shall be one-third of the total number of members including the Chairperson and the Member Secretary.~~ *One-fourth members of the Council including the Chairperson and the Member Secretary present in person shall form the quorum at every meeting of the Council: Provided that if within fifteen minutes from the time appointed for the meeting, no quorum is present, the meeting shall stand adjourned. The adjourned meeting may take place after two hours on that very day or as decided by the Chairperson. At such an adjourned meeting, no quorum shall be necessary and the members present may transact the business for which the meeting was called for.*

(6) The headquarter of the Council shall at such place, as may be specified by the State Government.

First Chairperson.

4. The first Chairperson of the Council shall be appointed by the State Government and shall continue as such till the Selection Committee selects a Chairperson *to be appointed by the State Govt.* under the provisions of this Act.

Advisory committee.

5. (1) There shall be an advisory committee consisting of three members who shall be reputed academician or famous intellectuals for ~~the selection~~ *preparing a panel for the selection committee for the appointment* of Chairperson of the Council.

(2) Out of the said three members, two members shall be nominated by the Council and one member shall be nominated by the State Government. (3)The member nominated by the State Government shall be the Chairperson of the Advisory Committee**.**

Chairperson.

6. (1) The tenure of the Chairperson shall be for a period of five years.

(2) The Chairperson may be removed by the State Government, if his work and conduct is found unsatisfactory.

7. The Selection Committee consisting of the following members shall select the Chairperson on the recommendation of the Advisory Committee, namely:- (a) the Speaker of the State Legislative Assembly;

(b) the Chief Minister;

(c) Leader of the Opposition in the State Legislative Assembly.

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

Vice-Chairperson

8. (1) The Vice-Chairperson shall be appointed by *the Govt. on the recommendations of* a three member committee for a period of five years. The Chairperson of the Council shall be the Chairperson of this committee. One member of the committee shall be nominated by the Council and one member shall be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chairperson may be removed on the recommendation of the Council.

Removal of member.

9. (1) The State Government shall remove a member if he,-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; (d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Council, absent from three consecutive meetings of the Council.

(2) On a controversy regarding the disqualification of a member, the decision of the *State Govt.* shall be final.

(3) No person shall be eligible to be nominated as a member of the Council unless he is a graduate**.**

Duties and functions of Council

10. The duties and functions of the Council shall be,-

(i) to implement the decisions of the Commission;

(ii) to frame policy of Higher Education for the State (Future Planning, Annual Planning and Budget);

(iii) to help the Higher Education Institutes of the State in planning and implementation;

(iv) to coordinate between the top institutes of education, regulatory bodies and State Government;

(v) to invigilate and implement the planning of Higher Education;

(vi) to manage, frame information system and its maintenance;

(vii) to collect data pertaining to Higher Education *from* Government ~~level~~ and institution level from time to time;

(viii) to evaluate the institutions of Higher Education in the State in accordance with the key performance indicators framed by National Higher Education Mission and if required, make parameters;

(ix) to plan and suggest measures for the continuous growth in teaching quality and research in the State;

(x) to suggest reforms in examination system;

(xi) to make syllabi contemporary and relevant;

(xii) to encourage innovation in research;

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

(xiii) to safeguard the autonomy of the institutions of Higher Education of the State;

(xiv) to grant permission for the establishment of new institutions, colleges *of higher education*;

(xv) to suggest measures to improve the procedures of the recognition;

(xvi) to advice the State Government on investments in Higher Education;
(xvii) to advice the universities in making Regulations and Acts;

(xviii) to manage the amount received as contribution of National Higher Education Mission through the State Government;

(xix) to make such procedures through which Grant in Aid of the State Government may be transferred to the institution of Higher Education;

(xx) to make and follow a transparent procedure to transfer the financial aid to universities and colleges under National Higher Education Mission.

Meetings of the Council.

11. (1) The meetings of the Council shall be held as per requirement. However, it shall be mandatory to convene at least *two meetings in a year* ~~one meeting in three months.~~

(2) The Member Secretary of the Council shall convene the meeting of the Council on the advice of the Chairperson.

(3) ~~The quorum of the meeting of the Council shall be one-third members of the total members of the Council.~~

Constitution of Commission.

12. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute the Haryana State Higher Education Commission under the Chairmanship of the Education Minister, Haryana and such other members, as the State Government may deem fit.

(2) The terms and conditions of the members of the Commission shall be such as may be specified in the notification.

(3) The Commission shall make recommendations and suggestions for academic excellence in the State.

Vacancy not to invalidate proceedings.

13. No act or proceedings of the Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the Council.

Resignation.

14. Any member may forward a resignation letter to the Chairperson but shall remain as a member till he is informed in writing that his resignation has been accepted by the Chairperson.

Allowances to members.

15. The members shall be entitled to receive such travelling allowances, daily allowances, local expenses and participation fees, as may be specified by the State Government *and adopted by the Council.*

Emergent vacancies.

16. (1) If any emergent vacancy occurs due to death, resignation, retirement or any other reason, the State Government shall nominate or appoint a member.

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

(2) The tenure of the new member shall be for the remaining tenure of that member against whom *she/*he is nominated or appointed.

Annual account and audit.

17. (1) The accounts of the Council and the annual report of accounts shall be maintained in such manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by an Auditor appointed by the Council.

(3) The Member Secretary shall be responsible for the publication of the annual report and make available the sealed copy of report to each member and presenting the same before the Council for approval.

(4) Mistakes and irregularities pointed out by the Auditor shall be rectified by the Council following due procedure.

(5) The audited report of the accounts of the Council shall be presented to the State Government within prescribed time limit alongwith the comments of the Council.

(6) After receiving the annual accounts and audit report, the State Government shall present it before the State Legislature as soon as possible.

Annual report.

18. (1) The Council shall present the annual report of its activities every year before the State Government.

(2) After receiving the annual report, the State Government shall present the same before the State Legislature at the earliest.

Protection of action taken in good faith.

19. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant or the State Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made there under.

Officers and employees of Council.

20. (1) The Council may appoint such officers and employees as may be deemed necessary for smooth functioning of the Council.

(2) The terms and conditions of the service of the officers and employees of the Council shall be such, as may be prescribed *by the Government for equivalent post and nomenclatures*.

Members, officers and employees of Council to be public servants.

21. The members, officers and employees of the Council shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Power to make regulations.

22. The Council may make such regulations which are not in contradiction of the provision of this Act and which are essential for the function of the Council**.**

Power to make rules.

23. The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties.

24. (1) If any difficulties arise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, make such provisions, which are not relevant to the provisions of this Act, which appear necessary or expedient.

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

(2) Any order made under this section shall be placed before the State Legislature.

25. (1) The Haryana State Higher Education Council Ordinance, 2018 (Haryana Ordinance No.3 of 2018), is hereby repealed. **Repeal and saving.**

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act**.**

KULDIP JAIN,
SECRETARY TO GOVERNMENT HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

*As per Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020- HARYANA ACT NO. 12 OF 2020

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

कार्यशालाएं – 18 से 21 अगस्त, 2020

रिपोर्ट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हरियाणा के संदर्भ में कार्यान्वित करने हेतु हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा 4 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 18 से 21 अगस्त, 2020 तक ऑनलाईन आयोजित की गई।

इन कार्यशालाओं में 250 से अधिक अध्यापकों, प्राध्यापको, मुख्याध्यापकों, विद्यालयों के प्राचार्यों, राजकीय एवं राज्य पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, राज्य पोषित विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों तथा अन्य शिक्षाविदों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशालाओं में 19 मुख्य प्रस्तुतिया दी गई तथा 77 शिक्षाविदों द्वारा सक्रिय रूप से सहभागिता एवं चर्चा की गई।

इन 4 दिवसीय कार्यशालाओं का आरम्भ माननीय महामहिम राज्यपाल के आशीर्वचन से हुआ। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहाः

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का मूल उद्देश्य कौशल, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में बदलाव के जरिए देश को बेहतर विद्यार्थी, व्यवसायी, पेशेवर और बेहतर इंसान देने का मार्ग प्रसस्त किया गया है।**
2. **रूचि अनुसार विषय के अध्ययन से हमारे विद्यार्थी विभिन्न विषयों में पारंगत होगें। इन विद्यार्थियों की प्रतिभा का लाभ देश को ही मिलेगा। इससे ब्रेन–ड्रेन को लगाम लगेगी।**
3. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान, नए अन्वेषणों तथा रोजगारान्मुखी कार्यक्रमो को लगातार तीव्रता प्रदान करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। स्वभाविक रूप से भविष्य में देश में शिक्षा से सम्बन्धित ढांचागत सुविधाओं का अपार विकास होगा।**

दिनांक 18.08.2020, समयः 12:00 से 02:00 अपराह्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–विद्यालयी शिक्षा

इस कार्यशाला में महामहिम राज्यपाल हरियाणा के आशीर्वचन के पश्चात विद्यालयी शिक्षा के बारे जो मुख्य अनुशंसाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई हैं उन पर डा॰ ऋषि गोयल, निदेशक PRARAMBH तथा SCERT द्वारा विस्तृत प्रस्तुति की गई। प्रस्तुति में उन्होंने

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की रचना विषय–वस्तु व प्रणाली में मौलिक परिवर्तन, बालक–बालिकाओं के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु में संस्कारित करने का प्रावधान, शत–प्रतिशत बच्चों का विद्यालय की शिक्षा, मातृभाषा में ही शिक्षा पर अधिक बल, सैकेण्डरी शिक्षा में विषयों के विभाजन को समाप्त करना, पुस्तकों का पुनर्लेखन, भारतीयता का समावेश और भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने बारे अनुशंसाओं को सांझा किया।

दिनांक 19.08.2020, समयः प्रातः 11:00 से 01:00 अपराह्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–उच्च शिक्षा

द्वितीय कार्यशाला 19.08.2020 को आयोजित की गई इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा बारे जो अनुशंसाएं की गई उन्हें प्रतिभागियों के साथ सांझा किया गया। इसमें मुख्य प्रस्तुतियां प्रो• टंकेश्वर कुमार कुलपति गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, प्रो• एच. एल. वर्मा कुलपति जगन नाथ विश्वविद्यालय बहादुरगढ़, प्रो• नरेन्द्र कुमार बिश्नोई गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार द्वारा की गई। प्रस्तुताओं द्वारा बहुविषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायतता देना, अध्यापको के प्रशिक्षण की विस्तृत व्यवस्था, भारतीय भाषाओं, कला व संस्कृति का विकास, शोध के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थानों की रचना, शिक्षा में मानवीय व भारतीय मूल्यों के समावेश, राज्यों में राज्य शिक्षा आयोग की रचना, नियामक संस्थाओं की पुनः रचना, शिक्षा में कौशल निपुणता की अनिवार्यता बारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई अनुशंसाओं को सांझा किया।

दिनांक 20.08.2020, समयः प्रातः 11:00 से 01:00 अपराह्न तथा 03:00 से 05:00 सायं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा हरियाणा के संदर्भ में

तीसरा व चौथा सत्र दिनांक 20.08.2020 को सम्पन्न हुआ। इन सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा के संदर्भ में समग्र रूप से लागू करने बारे प्रस्तुतियां दी गई।

विद्यालय शिक्षा की कार्ययोजनाओं बारे मुख्य प्रस्तुतियां डा• जगबीर सिंह अध्यक्ष हरियाणा राज्य विद्यालय बोर्ड, श्री सुनील बजाज उप–निदेशक SCERT गुड़गांव व अन्य द्वारा दी गई। दूसरे सत्र में उच्च शिक्षा बारे प्रस्तुतियां प्रो• बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद, प्रो• राजबीर सिंह कुलपति महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक, श्री राज नेहरू कुलपति श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, प्रो• राज कुमार मित्तल कुलपति चौ बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी, प्रो• एस.के. गक्खड़ कुलपति इंदिरा गांधी

विश्वविद्यालय मीरपुर, डा• विजय अरोड़ा प्राचार्य एल.एन.हिन्दू कॉलेज रोहतक इत्यादि–इत्यादि द्वारा की गई। इन प्रस्तुतियों में हरियाणा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करने हेतू प्रस्तावनाएं एवं सुझाव दिये गये।

इन सभी प्रस्तुतियों पर प्रो• बृज किशोर कुठियाला, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा गहन मंथन एवं चर्चा हेतु प्रतिभागियों से अनुरोध किया। विस्तृत चर्चा पर इस बारे यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुरूप ही हरियाणा के लिए कार्ययोजना समग्र शिक्षा के रूप में तैयार की जाए। इसके लिए एक सुदृढ़ शैक्षिक प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करने हेतु कार्यदल का गठन किया जाए जिसमें विद्यालयी, उच्च, तकनीकी, कौशल विकास इत्यादि सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हो।

दिनांक 21.08.2020, समयः 12:00 से 02:00 अपराह्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–समापन, निष्कर्ष व कार्ययोजना

कार्यशालाओं के पांचवें अन्तिम सत्र में इन कार्यशालाओं में जो मुख्य निष्कर्ष सामने आए तथा कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु शैक्षिक प्रबन्धन की प्रस्तावना दी गई उन्हें दिनांक 21.08.2020 को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने उदबोधन में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा किः

1. जैसा कि हम सब को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही पूर्व औपचारिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा को जोड़ा गया है। इसलिए सभी शिक्षण संस्थाओं ने नई शिक्षा नीति को बेहतर क्रियात्मक रूप देने के लिए सभी तरह के शैक्षिणक व एकैडमिक स्तर पर फ्रेमवर्क और मजबूत करना होगा।
2. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल, रोजगार, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं सब पैमानों पर खरा उतरने के लिए विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जोड़ना होगा ताकि दोनों संस्थाएं आपस में ताल–मेल कर डिप्लोमा, डिग्री, व्यवसायी कोर्स करवाकर युवाओं को रौचक विषयों व कार्यों में पारंगत कर सकें।
3. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक रूप से दबे–कुचले लोगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह अम्ल में लाना हम सब के लिए चुनौती होगी। इसके लिए हमें निजी संस्थानों के साथ बेहतर सामंजस्य करने की जरूरत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानदण्डों को अपनाते हुए यदि हम गरीब लोगों के लिए शिक्षा के सामान अवसर जुटा पाए तो यह देश के लिए गौरव की बात होगी।

मुख्य निष्कर्ष एवं कार्ययोजना

कार्ययोजना





निष्कर्ष एवं कार्ययोजना – 1

- आंगनवाड़ीयों का सशक्तिकरण
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को संस्कार की व्यवस्था
- अभिभावकों को दायित्वबोध
- ईसीसीई (Early Childhood Care & Education) की व्यवस्था

निष्कर्ष एवं कार्ययोजना – 2

भाषा

- 11–12 वर्ष की आयु तक मातृभाषा में शिक्षा
- बारहवीं तक मातृभाषा में शिक्षा का विकल्प
- 2 भाषाएं ओर सीखने और सिखाने की व्यवस्था
- उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा का विकल्प

निष्कर्ष एवं कार्ययोजना – 3

परीक्षा

- रटने का टैस्ट नही
- समझ और व्यवहारिकता का टैस्ट
- उच्च शिक्षा में जाने के लिए एक ही परीक्षा
- निरंतर मूल्यांकन
- पारदर्शिता
- परीक्षा व मूल्यांकन का बड़ा हिस्सा डिजिटल व ऑनलाईन

निष्कर्ष एवं कार्ययोजना – 4

उच्च शिक्षा – 1

- हर जिलें में औसतन 2 समग्र उच्च शिक्षा संस्थान (एक विश्वविद्यालय व एक महाविद्यालय)
- प्रत्येक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय की अल्पकालीन व दीर्घकालीन दृष्टि व योजना
- दृष्टि व योजना का हर 6 माह में अवलोकन
- सक्षम महाविद्यालय को स्वायत महाविद्यालय बनाना
- क्रमशः सम्बन्धता की प्रणाली को समाप्त करना
- विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का पुनः अवलोकन

निष्कर्ष एवं कार्ययोजना – 5

उच्च शिक्षा – 2

- हर पाठ्यक्रम में जीविका–उपार्जन के साधनों का प्रशिक्षण अनिवार्य
- हर पाठ्यक्रम में विषय से सम्बन्धित आचार–विचार व मूल्यों का समावेश
- हर पाठ्यक्रम में मानव मूल्यों का समावेश
- हर पाठ्यक्रम में भारतीय परिपेक्ष्य अनिवार्य
- हर पाठ्यक्रम में डिजिटल व ऑनलाईन सीखने वाले विषयों को चिन्हित करना
- एकल विषय (Stand alone) के महाविद्यालयों का अन्य विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में विलय

धारणा परिवर्तन (Paradigm Change)

पढ़ने–पढ़ाने
के स्थान पर
सीखने–सिखाने
का वातावरण

धारणा परिवर्तन (Paradigm Change)

शिक्षा का उद्देश्य

क्या सोचना ✗

कैसे सोचना ✓

इनके कार्यन्वयन हेतु परिषद द्वारा निम्नलिखित सुझाव/प्रस्ताव सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं :–

1. राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार एवं क्रियान्वित करने की घोषणा करें।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हरियाणा राज्य शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप तैयार किया जाए।
3. हरियाणा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने के लिए कार्यदल (Taskforce) बनाने की घोषणा करें।
4. सम्पूर्ण शिक्षा को समन्वित करते हुए कार्ययोजना बनाने के लिए 11 सदस्यों का कार्यदल (Taskforce) बनाया जाए (बिंदू–3) जो निर्धारित समय में तुरन्त, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यों को क्रियान्वित करने की योजना दे।
5. क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को समग्र रूप से देखा गया है इसलिए योजना व क्रियान्वयन के समय विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा और उच्च शिक्षा को एक ही कार्यदल व्याखित करें। कार्यदल में सभी का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए।

Sl. No.	Name of the University	Involvement of Alumni and representatives from industry and profession in Board of Academic Council of the Universities- Report to be submitted to Hon'ble Chancellor
1	J.C. Bose University, Faridabad	University has started inviting the representatives of alumni, profession, trade and industry as special invitees in the meetings of Board of Studies and the Academic Council.
2	Kurukshetra University, Kurukshetra	(a)Proposal is underway for one alumni/ representative from Industry to be added in UG BOS and modalities be the same as existing. (b)Two teacher's representatives, one alumni/ representative from industry be nominated as member in PG BOS (Proposal is underway for one alumni/ representative from Industry to be added in PG BOS). (c)Proposal is underway for two Alumni/ Representative from Industry/professionals be nominated as members of the Academic Council.
3	Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Sonipat	University has started its administrative as well as academic functioning from the current session i.e. 2019-20 and presently only 1 course is being run. The constitution of board of studies and academic council is under consideration. There is no need to review the curriculum.
4	Shri Vishwakarma Skill University, Gurugram	In the skill council, 3 experts from industries are nominated by chancellor of the University and this is to inform that out of 49 members in the council, 22 members are from industry/other organization. Three Vishwakarma Awardee (Awardee by Central Govt.) from the state or from the neighboring states are also nominated by the Chancellor. BOS for UG and PG courses has been constituted in which experts of industry are nominated as members and based on the inputs of Industry and other nominated members, courses are offered to synchronize the demand of skilled persons in the industry.
5	Chaudhary Ranbir Singh University, Jind	University issued a letter vide no. CRSU/Acad./AC-II/2019/8004-19 dated 17.01.2019 to all the Chairpersons of University Teaching Departments to re-constitute the Post Graduate Board of Studies & Research to include 1 representative in PGBOS & Industry and Profession, initially as special invitees. Further, to make the provision on permanent basis, this University has already got approved the amendment by the Executive Council, vide Resolution no. 31 in relevant clause Statute-30, 3(iv) for inclusion of one representative from Industry and Profession to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of concerned Chairperson. Accordingly, the amendment has already been sent to the Secretary to the Hon'ble Governor of Haryana & the Chancellor, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind for the assent of his Excellency.
6	Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Sonepat	All the Chairpersons/HODs/Incharges/Principals have been requested to include Alumni and representatives from industry and profession in Board of Studies in the first instance and they will be included in the Academic Council also by following due procedure in due course of time after making provision in the Statue of the University.
7	SUPVA, Rohtak	The representatives from industry and profession have been included in the University UG/PGBOS.
8	Gurugram University	The Chairpersons of various Departments have already been communicated to include the representatives of Industry and Profession in Board of Studies. Regarding Academic Council the matter is under active consideration for amendment in the relevant Statutes. In the mean time, the Industrialist relevant to the courses running in the University will be invited as Special Invitee deemed appropriate by the Vice- Chancellor.

9	Ch. Bansi Lal University, Bhiwani	Inclusion of names of Alumni and Representatives of Industry and Profession in the Academic Council and Board of Studies has been implemented. Further, the matter to amend the Statues was considered and approved by the Academic Council vide resolution no. 14 of its 3rd meeting held on 22.07.2020 and the same shall be placed before the Executive Council for its consideration and approval. After the approval of the Executive Council, the assent of the Hon'ble Governor-Chancellor will be obtained for inclusion in the Statue.
10	Maharshi Dayanand University, Rohtak	Matter with regard to framing the modalities for selecting the Alumni/Representatives as a member of UG/PG Board of Studies and Academic Council is under consideration by a committee constituted by the Vice Chancellor
11	Guru Jambheshwar University, Hisar	University has made a provision of four persons from public sector industries of the Central and State Govt. in the state having proficiency in matters relating to industry and research to be nominated by the Chancellor on the recommendations of the Vice Chancellor. University has also made a provision of up to two outside experts out of which one may be from industry to be nominated by the Vice Chancellor on the recommendations of the Dean of Faulty. Furthermore, university also nominates one outside expert from industry on the BOS&R as a special invitee and also going to make statutory provision in the constitution of BOS&R. However, there is no statutory provision for representative of Alumni in the Academic Council and BOS&R, but the university nominates the Alumni amongst the outside expert or industry expect on the Academic Council and BOS&R.
12	Ch. Devi Lal University, Sirsa	At university teaching departments will nominate one person from industry in the UGBOS and PGBOS&R of the concerned department.
13	Maharshi Balmiki Sanskrit University, Mundri, Kaithal	University has nominated representatives of alumni, profession, trade and industry in the academic council and board of studies. Necessary amendments in the statues are being carried out accordingly.
14	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Sonepat (DCRUST)	Following provisions are available in the Act and Statue of University:- 1. Four eminent educationists to be nominated by the Vice-Chancellor from outside the University: Provided that not more them one of them shall be from the same field. 2.Four persons from public sector industries of the Central and State Governments, in the State having proficiency in matters relating to industry and research, to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor.
15	Indira Gandhi University, Meerpur	University has decided to invite the representatives of alumni, profession and industry in the meetings of Academic Council and Board of Studies as Special Invitees. Amendments in Statues are being taken up accordingly.

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद
Haryana State Higher Education Council

हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित (अधिनियम सं. 4, वर्ष 2018)

प्रो० बृज किशोर कुठियाला
अध्यक्ष

क्रमांक 14/2-2020 HSHEC

दिनांक 15.09.2020

Subject: - Norms for opening new colleges.

*****

Hon'ble Chief Minister ji,
Namaskar.

Matter with a view to ensure that a college if opened has necessary infrastructure, faculty, student strength etc. for its smooth functioning and ensuring quality education has been engaging the attention of Haryana State Higher Education Council. Besides, there may be pockets in the State where facility for higher education needs to be provided despite lesser number of student strength etc..Therefore to explore the possibility and also to lay down norms where the State Government as a social commitment and various other factors may be required to provide facilities in the un-served pockets, the Council constituted a committee for suggesting norms for three models namely a college with (i) 100 student strength (ii) 100-200 student strength and (iii) student strength above 200.

The above task was entrusted to a group of following Principals for deliberations and putting up a detailed a comprehensive proposal:-

1. Sh. Desh Bandhu, Principal (Retd.), S.D. College Ambala Cantt
2. Mrs. Sushma, Principal (Retd.), DAV College Yamunanagar
3. Dr. Archna Mishra, Principal, G.C. Panchkula
4. Principal, Dyal Singh College, Karnal
5. Sh. Partap Singh Rohilla, Principal, G.C. Hisar

तकनीकी शिक्षा सदन, सैक्टर: 4, पंचकूला (हरियाणा) - 134109
संपर्क सूत्र : 0172-2570743, chairpersonhshec@gmail.com

The committee has submitted the report which is placed below at flag 'X' for kind perusal. The committee has touched upon and covered all the essential aspects for opening a new college initially with variable student strengths but with a vision for future expansion of such colleges and till then to be assisted by nodal cluster college/s as envisaged in National Education Policy-2020. The committee has also clearly spelt out the faculty needed for one stream, two streams and multi-disciplinary streams. Norms for infrastructure has also been clearly spelt out. Not only this, the committee has also recommended relaxation in terms of land in case of remote areas like Nuh and Morni Hills.

The Council would therefore recommend that the norms so proposed by the committee may kindly be considered by the State Government and the Department may keep these norms in view for initiating/recommending any proposal for opening a new college in the State.

The matter is accordingly submitted for your kind consideration/orders as deemed appropriate.

सादर।

(Prof. B.K.Kuthiala)

Shri Manohar Lal Khattar Ji,
Hon'ble Chief Minister,
Govt. of Haryana,
Chandigarh.

Detailed & Comprehensive Proposal of the Committee constituted by the Haryana State Higher Education Council vide their notification No. 14/2-2020 Adv./HSHEC dated July 27, 2020 to put-up a detailed & comprehensive proposalfor establishing new colleges in the unserved pockets of the Haryana state where the facility for higher education needs to be provided despite lesser number of students.

Members

1. Dr. Desh Bandhu, Principal (Retd.) S.D. College Ambala Cantt- Chairperson
2. Dr. Sushma Arya, Principal (Retd.), DAV College, Yamunanagar and Present Registrar, DAV University, Jalandhar (Punjab)
3. Dr. Archana Mishra, Principal, Government PG College, Panchkula
4. Dr. ChanderShekhar, Principal, Dyal Singh College, Karnal
5. Sh. Partap Singh Rohilla, Principal, G.C. Hisar – Member Secretary

To avoid social gathering because of pandemic COVID-19, the Committee could hold only two physical meeting on Aug 7, 2020 and 4th September 2020, rest three meetings were held virtually (through Jio or Zoom meet) on Aug 13, 2020, Aug 21, 2020 and Aug 28, 2020.

As per requirements of the Haryana State Higher Education Council, as are mentioned in its above quoted letter regarding three models of colleges namely **(A)**student strength of 100 **(B)** student strength of 100-200, and **(C)** student strength above 200, and also keeping in mind the New Education Policy – 2020 and the recommendations of the Kothari Commission the Committee after due deliberations on the holistic requirements, while opening a new college is of the unanimous view that following points must be kept in consideration while opening the new college.

I. Keeping in mind the expansion of the new college/s to multi-disciplinary/multi-faculty college/s having autonomous status in mind right decision regarding the location where the HEI is to be established is of utmost importance.

II. Total passing out strength of the feeding institutions of nearby areas be kept in mind.

III. The college clusters could be made which may consist of one large college having multiple disciplines as the nodal center and 4-5 colleges with lesser strength of students. More courses could be introduced in these clusters like professional, technical and vocational subjects and soft skills besides the traditional disciplines like science, social sciences, humanities, arts, commerce and languages and curriculum should be made multidisciplinary to give wider choice of subjects to the students.

IV. The colleges with smaller number of students and single or bi-faculty colleges be designated as stand- off colleges. However to give students an access to a

multiplicity of subjects these colleges should be made a part of the larger cluster of colleges from where online lectures could be delivered and made accessible to the students of these colleges located in the remote areas or they may be provided with transportation facility if they need to access the central library.

V. ***Following minimum requirements of Land, infrastructure and man power be kept in mind:-***

Land- Keeping in view the future requirements of the colleges, the Committee is of the view that the minimum land required for opening a new girls' college should be 5 acres and for a co-educational institution, it should be 8 acres.

However, in the initial stages / years, the construction in these colleges may be done as per the basic requirement which shall later on be built-up as per the need prevailing in the upcoming years. The land in excess of the built-up area, may be utilized for landscaping (to give an alluring ambience) and for sports facility etc.

For the **underserved and remote areas** like – Nuh and Morni and alike. establishment of new multidisciplinary colleges with minimum student strength of 100-200 relaxation in terms of land may be given.

VI. **Infrastructure**

The Committee is of the view that the following minimum infrastructure should be provided to the colleges before the commencement of admissions in the newly established college, which will boosts the confidence and morale of the students.

Colleges with student strength up to 100 with single faculty: (*However in the light of NEP-2020 which stresses on horizontal and vertical flexibility to students in terms of choice of subjects, single faculty colleges be discouraged*)

Class Room – 6

Principal Office – 1

Staff Room – 1

Administrative Office – 1

Girls' Common Room – 1

Boys' Common Room – 1 (In case of Co-education College)

Medical Room – 1

Library – 1

Computer Labs – 2

Language Lab – 1

Sports Room – 1

(81) (5)

Wash Rooms, separate for staff and students (both male and female).

Special facility for online education.

Play Grounds and indoor games facility.

VII. a. Colleges with the student strength 200-300 with single faculty:

10 class rooms in addition to all the facilities mentioned at V &VI above.

b. Colleges with the student strength of 200-300 with two streams i.e. Arts and Commerce:

13 Class Rooms in addition to all facilities mentioned in V & VI above plus one commerce lab and one separate computer lab for commerce students.

VIII. Colleges with the student strength up to 300 and above, multi-faculty i.e. Arts, Commerce and Science:

Class Rooms – 16 in addition to all facilities mentioned in V & VI above

Physics Labs – 2

Dark Room – 1

Chemistry Labs – 2

Balance Room / Instrumentation Room – 1

Botany Lab – 1

Zoology Lab – 1

Separate Computer Lab if Computer is opted as a subject in B.Sc.

Commerce Lab - 1

IX. General infrastructure requirements for all categories of colleges:

(i)

a.	Principal's Office	Table Chairs Showcase Sofa & Centre table Visitors' chairs LED TV & A.C. Almirah Computer Printer Internet Attached retiring & washing rooms
b.	Steno's Office	Table Chairs Visitors' chairs Air Cooler Almirah Computer Printer Internet

c.	General Office	Tables Chairs Air Cooler Almirah Computer Printer Internet
d.	Computer Awareness Lab	15 Computers (Cat. A colleges) 15 Computers (Cat. B) 30 Computers (Cat. C) UPS Computer Tables, Stools / Chairs Internet with networking A.C.
e.	Library	Bookshelves Magazine /Journals Display cabinets Reading Tables & Chairs Counter & Staff Chairs
f.	Drinking water facility	Water Filter (not R.O.) Water Chiller (not Coolers)
g.	Girls' Common Room	With attached washrooms
h.	Office rooms (with furniture)	NCC NSS Women Cell Bursar
i.	Washrooms	Separate for ladies, Gents, physically challenged and transgender
j.	Canteen	With Counter Tables & Chairs
k.	Open Stage for functions	
l.	CCTV Cameras	
m.	ICT Equipment and Intercom facilities	Interactive Boards Multimedia Projectors (at least in 2 rooms)
n.	Ramp	For physical challenged persons

Note: The buildings should be designed in such a way that the construction should be vertical leaving more open area for future.

(ii). Library:-

In this era of ICT in addition to traditional library, the E-resource centres (digital libraries) should be established so that information in the digital form can be viewed from outside the campus.

(iii). Transport:=

The bus pass facility for the students of that particular region where the new college is proposed to be opened, should discontinue in order to get the optimum strength of students in the newly established college of that particular region subject to the condition that the subjects being opted by the student is available in the college of his / her region. In addition, transport arrangements be made available to the students especially girl students to visit cluster college to consult library and utilize other advance facilities.

(iv). Teaching, Non-Teaching and Staff Requirement:-

The Committee is of the view that teaching, non-teaching and support staff should be appointed on permanent basis so that accountability can be fixed.

The requirement of Teaching, non-teaching and support staff up to strength of 300 students, is as under:

a. Principal – 1

(The post of the Principal should be permanent and there should not be a dual charge of some other college(s).

b. Faculty – As per annexure of work load attached as annex 1
c. Head Clerk-cum-Accountant/ Deputy Superintend – 1
d. Clerk – 2-3
e. Steno-typist – 1
f. Data Entry Operator – 1
g. Peon – 2
h. Chowkidar – 3
i. SafaiKaramchari – 2
j. Mali – 1
k. Librarian – 1
l. Library Assistant – 1
m. Library Restorer – 1
n. Lab Attendant – 2-5

X. Students' Strength:-

For optimal use of faculty and infrastructure, the Committee is of the unanimous view that the students' sanctioned intake in the colleges to be established may be increased from 100, 200 and 300 to 160, 240 and 320, respectively. The faculty requirement, in

both cases will, however, remain the same as there will be a no change in the number of sections (maximum 80 students per section) (Workload calculated as per the attached sheet).

Cat. A – 160 students (2 Sections)

Cat. B – 240 students (3 Sections)

Cat. C – 320 students (4 Sections)

XI. Curriculum:-

1. Syllabi:-

The syllabi should be framed keeping in view the requirements of 3 year, 4-year undergraduate or 5-year integrated courses as per NEP-2020.

2. Option to choose subject (from other stream) running in his / her own college or at other college(s) in his / her cluster:-

To cater to the multi-disciplinary concept of the NEP-2020, the Committee is of the opinion that:

i. The students may be given a chance to opt for a subject of other stream(s) running in that particular college.

ii. Students enrolled in the college of his vicinity, may be allowed to opt any of the subjects running in other colleges of that particular cluster. However, the online study will be made available to avoid commuting from one place to another.

3. Online Education:-

In the subjects where the strength is less, instead of dividing the workload of a teacher in days at more than one stations, the online mode of teaching can be adopted by linking more than one colleges with the main / nodal college. For this, all colleges of the cluster must be equipped with high quality Wi-Fi facility.

4. Skill-based /add-on/ vocational courses

To impart education capable of generating employability after attaining degree, some vocational, skill-based courses / subjects / topics should also be added in the main curriculum as stated in NEP – 2020. Though the range of such courses is very wide, a few examples are given below; the choice may depends on socio-economic and geographic area of a particular region.

(85) (9)

More stress should be put on short duration courses of computers, communication and soft skills.

a. Apiculture or Fish Farming as a paper in the subject of Zoology.

b. Mushroom Culture as a paper in the subject of Botany.
(in the colleges where medical stream is allotted)

c. Certificate Course in Photography & Photoshop.
(it can be taught by teachers of Mass Communication and Computer)

d. Fashion Designing

e. Jewellery Designing

f. Interior Designing

g. Fine Arts

h. Architecture

i. Psychology

j. Applied History

k. Digital Marketing

l. Basics of Computer and Accounting
(by simply adding ledger & accounting topic in Computer Awareness Level-II certificate course).

m. Topic 'Corel DRAW' may be added in Computer Awareness Level-III certificate course.

(The names of Computer Awareness Level-II & III certificate course may be changed accordingly so as to reflect inclusion of new topics in their title name e.g. Basics of Computer and Accounting)

Some more skill-based courses may be started in those colleges where no ITI or Polytechnic College exists in the nearby areas. For this, the guidance may be sought from the Skill Development Councils and Polytechnics of the state. The MoUs in this regard may also be executed later on for practical trainings of students, if need be.

A Startup- Cum- Incubation Centre should be opened up in every district to provide the students with 'necessary guidance, technical support, access to investors, networking' etc. to start their own innovative start-up businesses. These centers should provide suitable infrastructure, mentoring by experts, business planning and management support, access to capital to be invested and should make available all other resources required for a start –up to survive and sustain in the competitive market.

The services of former Principals/teachers be utilized for mentoring and counselling.

Status of the college:-

To get the optimal strength, the colleges should be co-educational.

4/9/2020
(Sh. Partap Singh Rohilla)

(Dr. Chander Shekhar)

4/9/2020
(Dr. Archana Mishra)

4.09.20
(Dr. Sushma Arya)

04/9/2020
(Dr. Desh Bandhu)
Chairperson

Annexure

Basic Work Load of College

Subject	B.A. I	B.A II	B.A. III	B.Com. I	B.Com. II	B.Com. III	B.SC. I	B.SC. II	B.SC. III	Total Workload	Teacher Required
English	12	12	12				8			44	2
Hindi	6	6	6					8		26	1
History	8	8	8							24	1
Political Science	6	6	6							18	1
Economics	6	6	6	6						24	1
Commerce				24	36	36				96	4
Mathematics	18 (with B.Sc.)	18 (with B.Sc.)	18 (with B.Sc.)	6			18	18 + 12 Practical	18	72	3
Physics							18	18	18	54	2
Chemistry							18	18	18	54	2
Botany							18	18	18	54	2
Zoology							18	18	18	54	2
Computer Education											2
Environment Edu.											1 From Botany and Zoology
Physical Edu.											1
Library											1

HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

Tel. No. : 0172-2570743
E-mail : chairpersonhshec@gmail.com

Takniki Shiksha Sadan
Bays No. 7-12, Sector – 4,
Panchkula – 134112.

No. 3/49-2021 Adv./HSHEC
Dated: 10.01.2022

To,

The Director General,
Higher Education & Technical Education Departments,
Panchkula

Sub.:- Introduction of short term Certificates/Diplomas.

*****

Respected Sir,

Namaste

Greetings of the day

A copy of proposal alongwith report of the committee on the subject cited above is hereby shared with the Department for further necessary action as per orders of Hon'ble CM.

Regards

K.K. Agnihotri
Advisor, HSHEC

CC:-

1. Sr. Secy./APSCM for kind information of APSCM
2. PS/PSHE&TE for kind information of PSHE&TE

HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL

Sub.:- Short duration Certificate/Diploma courses

*****

Diary No.:- 184/HSHEC
Dated: - 15.11.2021

Haryana State Higher Education Council is facilitating and coordinating implementation of NEP-2020 which the State Govt. is committed to implement in letter and spirit and for that the Govt. has declared that the most of parameters oh which would be translated into action by 2025 as against National targets of 2030.

The respective Departments of State Govt. and the Universities have initiated various processes at their level by identifying deliverables and fixing the time frame.

A lot of emphasis has been laid in skilling the students along with education being imparted to them through various streams. These have been captioned as 'Equity and Inclusion in Higher Education-para 14' 'Reimagning Vocational Education- para 16' 'Professional Education -para 20' and so on.

The Council therefore constituted a committee comprising of the following:-

1. Dr. Desh Bandhu, Former Principal S.D. College, Ambala Cantt. – Chairman
2. Dr. Sushma Arya, Former Principal D.A.V. College for Girls, Yamunanagar
3. Dr. (Mrs.) Archana Mishra, Principal Govt. College , Sector-1, Panchkula
4. Dr. Rishi Pal, Former Principal Govt. College, Kaithal
5. Dr. Rajinder Singh, Principal, S.D. College, Ambala Cantt
6. Dr. (Mrs.) Rekha Sharma, Former Principal Govt. College, Karnal
7. Dr. S.K. Mishra, Former Principal Govt. College, Hisar

The committee has submitted a detailed report which is flagged as 'A' for kind perusal. The committee suggested short term courses which can be useful to the students to make them job worthy or entrepreneur. The salient feature is that these courses can be taken up by the students irrespective from any stream. Further these certificate/diploma courses with duration of six months/one year have been categorized in three categories viz job oriented, entrepreneurship and value added.

This is a good exercise carried out by the committee. Therefore after consideration of the matter the Council proposes as under:-

1. Department of Higher Education may share this report with Govt., Govt. Aided Colleges, and Universities for their consideration.
2. The Institutions/Universities be encouraged to introduce these courses along with regular stream. For this the Institutions may work out the details, implementation plan and share with the HSHEC and Department. No formal approval should be mandatory in such courses
3. The Institutions should be given the freedom to shortlist existing faculty who will impart instructions over and above their defined workload with additional remuneration to be worked out at Institutional level. If not possible, then contract faculty for a fixed duration or

हरियाणा सरकार

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

Diary No. (File) 5550
Dated 01/12/2021
07/01/2022

modular approach and decide the mode of payment as pr coverage of course content

4. The Institutions would be given the freedom to decide course fee with concessions to deserving students who are not in a position to pay
5. The entire income be kept in a separate account and the surplus be utilized for strengthening the facilities in the concerned courses
6. Preparation should start from the current academic session and the courses be introduced with all readiness from next academic session

If approved, the above proposals be submitted to Hon'ble CM for kind consideration/approval in principle and thereafter these will be shared with the Department accordingly for follow up action please.

29.X.2021
K.K. Agnihotri
Advisor, HSHEC

K.K. AGNIHOTRI
Advisor
Haryana State Higher Education Council
Panchkula

for consideration & approval.

Chairperson

30.11.2021
प्रो॰ बृज किशोर कुठियाला
अध्यक्ष
हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद

Hon./CM

CM has been apprised. He has desired the report be shared with the depttt for further w/a

6/1/22
(Dr. Amit K. Agrawal)
Addl. PSCM

Chairperson

HSHEC, Panchkula
Dated 21.12.2021

O/NO
49-2021
AHSHEC
X11.2021

May share the report with PSHE and with DG HE & TE with a request that the Council may be kept informed about the actions taken

BKK

HSHEC 9.1.2022
No 3/49-2021 Adm/HSHEC dt 10.1.2022

(4) (91)

REPORT ON SHORT DURATION CERTIFICATE/DIPLOMA COURSES FOR COLLEGES.

The Chairman,
Haryana State Higher Education Council,
Panchkula (Haryana)

Subject:- SHORT DURATION CERTIFICATE/DIPLOMA COURSES FOR COLLEGES.

Sir,

Reference to Memo No 3/49 – 2021 Adv./HSHEC dated 22.09.2021, a committee consisting of

1. Dr. Desh Bandhu, Former Principal S.D.College, Ambala Cantt.as Chairman
2. Dr. Sushma Arya, Former Principal D.A.V. College for Girls, Yamunanagar
3. Dr. (Mrs.) Archana Mishra, Principal Govt. College, Sector 1, Panchkula
4. Dr. Rishi Pal, Former Principal Govt. College, Kaithal
5. Dr. Rajinder Singh, Principal, S. D. College, Ambala Cantt.
6. Dr. (Mrs.) Rekha Sharma, Former Principal Govt. College, Karnal
7. Dr. S.K. Mishra, Former Principal Govt. College, Hisar

Was constituted to recommend a few short duration courses for the colleges to make students job worthy.

The first meeting of the committee was held on 28th September 2021 at S. D. College, Ambala Cantt to discuss the modalities to look for the short term courses which can be useful to the students to make them job worthy or entrepreneur and also value added courses which will help them in their job or business carrier.

After large rounds of virtual interaction among team mates a good number of such courses were worked out, many of which are being successfully being run in a few colleges. These courses were categorized in three categories viz. Job Oriented, Entrepreneurship and value added courses. The courses were further grouped in various streams/subjects.

While framing the co[illegible] and syllabi care was taken that the students from any faculty can study any of these courses.

The committee members are of the opinion that duration of certificate courses will be six months/one semester and that of Diploma will be one year/one academic session. Ultimately the duration and any addition/subtraction is left to the wisdom of various board of studies of different Universities.

List of proposed Certificate/Diploma courses along with the syllabi is enclosed for kind consideration of the Hon'ble commission.

Dr. Desh Bandhu | Dr. Sushma Arya | Dr. (Mrs.) Archana Mishra

Dr. Rishi Pal | Dr. Rajinder Singh | Dr. (Mrs.) Rekha Sharma, | Dr. S.K. Mishra

(5) (92)

List of short duration Certificate/Diploma Courses

S.No	Job oriented courses	Page No.	S.No	Entrepreneurship courses	Page No.	S.No	Value added courses	Page No.
	COMPUTER			**HOME SCIENCE**			**COMMERCE**	
1	Comp Aided accountancy (Tally)	1	E-1	Block Printing	91	VA-1	Personal Grooming	115
2	Comp App in Commorce/Management/Business	1	E-1A	Block Printing	95	VA-1A	Personal Grooming	119
3	System Applications & Product in Data Processing (SAP)	1	E-2	Embroidry	91	VA-2	Leadership and teamwork	115
4	Software and app development	1	E-2A	Embroidry	97	VA-2A	Leadership and teamwork	121
5	Cyber Security	1	E-3	Beauty and wellness	91	VA-3	Professional etiquattes	115
5A	Cyber Security	9-16	E-4	Handicraft	91	VA-3A	Professional etiquattes	123
6	Ethical Hecking	2	E-5	Bakery, confectionary and cookery	91	VA-4	Group Discussions	115
6A	Ethical Hecking	17-21	E-6	Food and Beverage Production	91	VA-4A	Group Discussions	125
7	Microsoft certification	2	E-6A	Food and Nutrition	99	VA-5	Interview Skills	115
8	Computer networking	2	E-7	Fashion Technology & Apparel Designing	91	VA-5A	Interview Skills	127
8A	Computer networking	23-27	E-7A	Apparel Designing	101	VA-6	Professional grooming	115
	Desk top publishing	2	E-8	Jewellery Designing	91	VA-7	Time management	115
9A	Desk top publishing	29-34	E-9	Cutting, Tailoring & Surface Ornamentation	91	VA-8	Stress Management	115
9B	Desk top publishing	35	E-9A	Cutting, Tailoring & Surface Ornamentation	103		**LANGUAGES**	
10	System administration with LINUX	2	E-10	Fashion Designing	91	VA-9	Public Speaking	115
10A	System administration with LINUX	37-42	E-11	Dairy Products and Processing	92	VA-9A	Public Speaking	129-130
11	Network administration	2	E-12	House Keeping and Management	92	VA-10	Creative writing	115
11A	Network administration	43-46	E-13	Vastu Shastra and Interior Designing	92	VA-11	Spoken English & Communication Skills	116
12	Database administration	2	E-13A	Basics of Interior Decoration	105	VA-12	Critical Thinking	116
12A	Database administration	47-50		**COMMERCE**			**HUMANITIES**	
13	Oracle SQL and PLSQL	2	E-14	Entrepreneurship development	92	VA-13	Gender Equality	116
	PCP design and assembly	3	E-15	Women Enterpreneurship	92	VA-14	Life skills (Emotional intelligence, Team Dynamics, Managing Diversity)	116
15	PC maintenance and networking	3				VA-15	Human Values and ethics	116

Rajinder

16	Office automation and Tally	3
17	Computer application and Information Technology	3
18	Information Technology & Retail Management	3
19	Networking & Mobile Applications	3
20	Graphic Desiging	3
21	Digital Marketing	3
21A	Digital Marketing	51-52
22	Web Designing	4
23	3 D Animation	4
24	Data Science	4
25	Programming with Phyton	4
25A	Programming with Phyton	53
26	Data Entry operator	4
27	Artificial Intelligence in Health Care & Bio Technology	4
28	Hardware & Technology	4
29	Office automation and E - Governance	4
29A	Web Designing using HTML	55-57
29B	Open Source Software	59-61
	COMMERCE	
30	Digital Marketing	5
31	Export, import & Logistic Mgt	5
32	E. Return Filling (Direct Taxatation and law	5
33	GST	5
34	E - Business	5
35	Typing & Short Hand English	5
35A	Typing & Short Hand English	63-64
36	Typing & Short Hand Hindi	5

	BIOLOGY	
E-16	Soil Mangement & Vermi - composting	92
E-16A	Vermicomposting	107
E-17	Landscaping	92
E-18	Rain Water Harvesting	92
E-19	Ornamental Fish Culture	92
E-20	Mushroom Cultivation	92
E-20A	Mushroom Cultivation	109
E-21	Bio farming	92
E-21A	Bio farming	111
E-22	Horticulture and Nursery Management	93
E-22A	Horticulture and Nursery Management	113
E-23	Landscape Gardening & Management	93
E-24	Green House Technology	93
	MUSIC/THEATRE	
E-25	Theater and stage craft	93
E-26	Western Contemporary Dance	93
	PHYSICAL EDUCATION	
E-27	Panchkarma	93

	CHEMISTRY	
VA-16	Chemistry in day today life	116
	SCIENCE/HUMANITIES	
VA-17	Research Methodology	116
VA-17A	Research Methodology	131
	MUSIC	
VA-18	Rhythm: Course on Music Instruments	117
VA-18A	Rhythm: Course on Music Instruments	133-134
VA-19	Sound Design & Music Voval	117
VA-19A	Sound Design & Music Voval	135-136
	COMPUTER	
VA-20	Power Point Presentation	117
VA-20A	Power Point Presentation	137-138
	General	
VA-21	Creative skills: Art & Craft	139
VA-22	Impromptu Speaking & Stage Management	141
VA-23	Personality Development and Professional Groming	143
VA-24	Circuit Design on PCB	145
VA-25	First Aid & Home Nursing	147

37	Taxation	5
37A	Taxation	65
38	Advertising & Marketing Communications	5
38A	Advertising & Marketing Communications	67
39	Business Management	5
39A	Business Management	69
40	Banking and Finance	5
41	Store Operation in Retail Marketing	5
42	Banking and Financial Sevices	5
	PHYSICAL EDUCATION	
43	Yoga and Meditation	5
44	Self defence skills	5
45	Aerobatics and Fitness	5
46	Course on sports coaching	5
47	Course on sports technology	5
48	Course on sports fitness	6
49	First aid training	6
	HOME SCIENCE	
50	Food Science and nutrition	6
51	Interior Desiging	6
52	Hospitality Management	6
53	Food Security	6
53A	Food Security	71
	CHEMISTRY	
54	Soil & Water testing assistant	6
	PHYSICS	
55	Refrigiration & Airconditioning	6
56	Photograpy	6
	BIOLOGY/ ENVIORNMENT SCIENCE	
57	Enviornment Security	6
58	Waste Management	6
58A	Waste Management	73-75
58B	Waste Management	77
[illegible]	Energy Security	6
59A	Energy Security	79
59B	Environmental Impact Assessment	81